the Labour Minister to make a statement, because two lakhs workers are on strike and the entire economy of Bengal is affected by this.

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): I support Shri Banerjee. I have also given notice of a Calling Attention. The matter is very important. So, it should be answered by the Labour Minister and not by Shri B. R. Bhagat.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Sir, I would suggest that the names of those hon. Members who have given notice of the Calling Attention should be included in the Short Notice Question because the subject is the same. Instead of the Calling Attention, you have been pleased to admit it as a Short Notice Question.

MR. SPEAKER: I quite agree with you.

श्वी शिव चन्द्र सा (मघुवनी) : काल अटेंशन मंजूर करना चाहिए था ताकि सब लोगों को मौका मिलता । ऐसा मालूम होता है कि किसी सदस्य ने मंत्री से बात की और आपस में बात करके तय कर लिया।

प्राप्यक्ष महोदय : मैं जब खड़ा हूँ तो झाप मत खड़े होइये । As suggested here, I will ask the Labour Minister to reply to the questions. Then, the names of those four Members would be included.

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL_contd. Clause 2— contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the Lokpal and Lokayuktas Bill. Almost the whole of the time allotted for this Bill has been exhausted and only twenty minutes are left. We are still on clause 2. As far as possible, the time allotted by the Business Advisory Committee must be adhered to.

बी बि॰ प्र॰ मंडल (मघेपुरा) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिये हैं उसमें कुछ ग्रोरिजिनल टाइप के हैं। जैसे मने कहा ह कि on page 2, line 7 after "improper or" insert "discriminatory or". कहने का मतलब यह है कि भारतवर्ष में हम लोग दूनिया भर के फिरकों में बंटे हुए हैं, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन ग्रौर प्रोविन्सेज में बटे हए हैं ग्रीर मुझे दूख के साथ कहना पडता है कि हिन्दुस्तान में बल्क आफ दी पीपल बैकवर्ड हैं ग्रौर चाहे मिनिस्टी हो, चाहे सर्विसेज हों, उसमें वे लोग नहीं हैं। इसलिए डिस्किमिनेशन होता है, कास्टिज्म होता है, इसलिए बिल में यह स्पेसिफिकली प्रोवीजन होना चाहिए कि जाति पाति के नाम पर जो पक्षपात होता है उसको भी लोकपाल ग्रौर लोकायक्त देखें ।

दूसरा मेरा संशोधन यह है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस बिल में शामिल करना चाहिये श्रौर प्रेसीडेंट को श्रधिकार होना चाहिये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चार्ज ला सर्के ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मिनिस्टर ग्रौर सेकेटरी को एक केंटेगरी में रखा गया है ग्रौर यह व्यवस्था की गयी है कि सेकेटरी ग्रीर मिनिस्टर के खिलाफ ग्रगर कोई चार्ज लाया जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर लायेगा । मैं संशोधन करना चाहता हं मिनिस्टर के खिलाफ जो कोई चार्ज हो तो प्राइम मिनिस्टर ला सकते है। श्रौर सेक्रेटरो के खिलाफ़ कोई च जे हो तो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं, क्योंकि सेकेटरी ग्रौर मिनिस्टर को एक केटेगरी में रखना ठीक नहीं है । हमको भी प्रदेश में मिनिस्टर ग्रौर चीफ मिनिस्टर रहने का मौका मिला है इसलिए में जानता है कि मिनिस्टर ग्रौर सेकेटरी को एक ग्रेड में रखना ग्रच्छा नहों है । इसलिए बिल में जहां तक सेकेटरी का सवाल है उसमें कर दिया [श्रीबि० प्र० मंडल]

जाए कि उसको कम्प्लेन्ट करने वाला मिनिस्टर इप्राफ दी डिपार्टमेंट कन्सर्न्ड होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा । और जहां तक मिनिस्टर का सवाल है उसके खिलाफ चार्ज लगाने का ग्रधिकार प्राइम मिनिस्टर को होगा ।

बिल में काउन्सिल ग्राफ मिनिस्टर्स श्राया है, लेकिन सदन में बहस के दौरान कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर विल नाट बो इनक्लडेड । क्या क उन्न्सिल आफ मिनिस्ट र्न को कोई यहा डे होनी झन बनाना चाहते हैं ? वाकई में काउन्सिल ग्राफ़ मिनिस्टर्स इनक्लंडस दी प्राइम मिनिस्टर । जब भी कभी ग्रविश्वास का प्रस्ताव सदन में ग्राता है तो वह काउन्सिल ग्राफ़ मिनिस्टर्स के खिलाफ त्राता है, न कि प्राइम मिनिस्टर के । प्रधान मंत्री काउन्सिल ग्राफ़ मिनिस्टर्स का प्रथम व्यक्ति होता है, यही परिभाषा सभी जगह मान्य है। तो जब बिल में काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स शब्द है ग्रौर उसके खिलाफ लोकपाल ग्रौर लोकायक्त को ग्राधिकार होगा तो फिर मेरी समझ में नहीं त्राता कि यह कहना कहां तक उचित है कि प्रधान मंत्री इसमें शामिल नह होगा । यह कहां तक सही है ? इतलिए प्राइम गिनिस्टर को भी काउन्सिल ग्राफ़ मिनिस्ट ग के बाद इनमर्ट करना चाहिए---इनक्लडिंग दी प्राइम मिनिस्टर । ग्रौर ग्रन्त में जहां मिनिस्टर शब्द है वहां मैं पार्लियामेंटी सेकेटरी को इन्सर्ट करना चाहता हं।

मेरा लास्ट जमेंडमेंट यह है कि

म्राध्यक्ष महोदयः ग्राप बंल लोजिए, ग्रलग-ग्रलग संशोधन मूव करने की जरूरत नहां है । ग्रमेंडमेंट ग्राप ें: मूब्ड समझे जायेगे ।

श्वो बि॰ प्र॰ मंडल ः मेरा यह कहना है कि मैं इससे कभी भी सहमत नहों हूं कि 'प्राइम मिनिस्टर ग्रौर लीडर ग्राफ दी ग्रपो-जीशन की राय से लोकपाल का ग्रपोइंटमेंट इडो । लोकपाल को पोलिटिकल इनफ्लूयेंस छे फी रखना चाहिये । प्राइम मिनिस्टर भी किसी पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं और लीडर ग्राफ़ दी प्रपोजीशन भी किसी पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं । इतलिए मेरा कहना है कि एक पैनल होना चाहिये नाम का, जिसमें एक नाम चीफ़ जस्टिस ग्राफ़ इंडिया की तर्फ से होना चाहिये, एक नाम कम्प-ट्रोलर ऐंड ग्राडिटर जनरल का होना चाहिए और एक नाम स्नीकर ग्राफ़. दी लोक सभा का होना चाहिये, ग्रीर तीन नामों फे पैनल में से प्रेसीडेंट एक ग्रादमी को लोकपाल ग्रापोइट कर ले । यही मुझे कहना है ।

MR. SPEAKER: I will put the amendments now to the vote of the House. Should I put them together?

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI: (Krishnagar): Sir, I have an amendment to clause 2.

MR. SPEAKER: Now there is no use. Only a few minutes are left. Now I am going to rush through the Bill.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul): Sir, it would not be fair to conduct the debate in a manner that certain important clauses will remain undebated in the House at all at this stage. Adequate time should be allowed on certain important clauses.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI: Sir, I may be given one minute to move my amendment.

MR. SPEAKER: Better not move it because it is going to meet the general fate.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): We want to press amendment No. 91.

SHRI S. KUNDU (Balasore): Include 95 also.

MR. SPEAKER: I am putting amendment No. 91 to the vote of the House. The question is: Page 2, after line 12, insert— "(i) in the case of

the Prime Minister

President of India

 (ii) in the case of members of Lok Sabha
Speaker of Lok Sabha

- (iii) in the case of Members of Rajya Sabha
- Chairman of the Rajya Sabha" (91)
- The Lok Sabha divided:

Division No. 19]

[12.45 hrs.

17. 7

VAES

Ahmed, Shri J. Amin, Shri R. K. Banerjee, Shri S. M. Bharati, Shri Maharaj Singh Chaudhuri, Shri Tridib Kumar Daschowdhury, Shri B. K. Deb, Shri D. N. Dwivedy, Shri Surendranath Gowda, Shri M. H. Jha, Shri Shiva Chandra Joshi, Shri S. M. Kapoor, Shri Lakhan Lal Kothari, Shri S. S. Kundu, Shri S. Kushwah, Shri Yaswant Singh Limaye, Shri Madhu Mandal, Shri B. P. Mangalathumadam, Shri Misra, Shri Janshwar Misra, Shri Srinibas Mohammed Imam, Shri J. Molahu Prasad, Shri Patel, Shri J. H. Ram Charan, Shri Samanta, Shri S. C. Shah, Shri T. P. Sharma, Shri Beni Shanker Shastri, Shri Prakash Vir Shastri, Shri Raghuvir Singh Shastri, Shri Shiv Kumar Suraj Bhan, Shri Thakur, Shri Gunanand Viswambharan, Shri P. 1905 (ai) LS----16.

NOES

Achal Singh, Shri Aga, Shri Ahmad Ahirwar, Shri Nathu Ram Ahmed. Shri F. A. Awadesh Chandra Singh, Shri Azad, Shri Bhagwat Jha Babunath Singh, Shri Barua, Shri Bedabrata Bhagat, Shri B. R. Bhagavati, Shri Bhandare, Shri R. D. Bhanu Prakash Singh, Shri Bhargava, Shri B. N. Bhattacharyya, Shri C. K. Bohra, Shri Onkarlal Bramhanandji, Shri Swami Chanda, Shrimati Jyotsna Chandrika Prasad, Shri Chatterji, Shri Krishna Kumar Chaturvedi, Shri R. L. Chavan, Shri Y. B. Chaudhary, Shri Valmiki Choudhury, Shri J. K. Dasappa, Shri Tulsidas Dass, Shri C. Dinesh Singh, Shri Ering, Shri D. Gandhi, Shrimati Indira Ghosh, Shri Parimal Girja Kumari, Shrimati Hanumanthaiya, Shri Hari Krishna, Shri Hazarika, Shri J. N. Himatsingka, Shri Jadhav, Shri Tulsidas Jagjiwan Ram, Shri Jamir, Shri S. C. Jamna Lal, Shri Kamble, Shri Karan Singh, Dr. Kavade, Shri B. R. Kesri, Shri Sitaram Khan, Shri M. A. Kinder Lal, Shri Krishna, Shri M. R. Krishnappa, Shri M. V. Kureel, Shri B. N. Lakshmikanthamma, Shrimati Laskar, Shri N. R. Laxmi Bai, Shrimati Lutfal Haque, Shri Mahadeva Prasad, Dr. Malhotra, Shri Inder J. Mane, Shri Shankarrao Melkote, Dr.

AUGUST 20, 1969

Lokayuktas Bill 452

Menon, Shri Govinda Minimata Agam Dass Guru, Shrimati Mirza, Shri Bakar Ali Mishra, Shri Bibhuti Mishra, Shri G. S. Mohsin, Shri Mukerjee, Shrimati Sharda Mukne, Shri Yeshwantrao Murti, Shri M. S. Palchoudhuri, Shrimati Ila Pandey, Shri K. N. Pande, Shri Vishwa Nath Panigrahi, Shri Chintamani Pant, Shri K. C. Paokai Haokip, Shri Parmar, Shri Bhaljibhai Parthasarathy, Shri Patil, Shri Deorao Patil, Shri S. D. Poonacha, Shri C. M. Raghu Ramaiah, Shri Raju, Dr. D. S. Ram, Shri T. Ram Dhan, Shri Ram Sewak, Shri Chowdhary Ram Swarup, Shri Rana, Shri M. B. Rane. Shri Rao, Shri Jaganath Rao, Shri Muthyal Rao. Shri Thirumala Raut, Shri Bhola Roy, Shri Bishwanath Roy, Shrimati Uma Sadhu Ram, Shri Saha, Dr. S. K. Saigal, Shri A. S. Salve, Shri N. K. P. Sanghi, Shri N. K. Sanji Rupji, Shri Sankata Prasad, Dr. Sant Bux Singh, Shri Sapre, Shrimati Tara Savitri Shyam, Shrimati Sayyad Ali, Shri Sen, Shri Dwaipayan Sen. Shri P. G. Sethi, Shri P. C. Shambhu Nath, Shri Shastri, Shri Sheopujan

Sheth, Shri T. M. Shiv Chandika Prasad, Shri Shukla, Shri Vidya Charan Siddayya, Shri Siddheshwar Prasad, Shri Sinha, Shri Mudrika Sinha, Shri R. K. Sonar, Dr. A. G. Sonevane, Shri Surendra Pal Singh, Shri Swaran Singh, Shri Tiwary, Shri D. N. Vyas, Shri Ramesh Chandra Yadab, Shri N. P. Yadav, Shri Chandra Jeet MR. SPEAKER: The result of the division is: Aves: 33; Noes: 120 The motion was negatived. MR. SPEAKER: I shall now put all the other amendments together to the vote of the House. The other amendments* were put and negatived. MR. SPEAKER: The question is: "That Clause 2 stand part of the Bill." The motion was adopted Clause 2 was added to the BilL Clause 3-(Appointment of Lokpal and Lokayuktas.) SHRI OM PRAKASH TYAGI; मरादाबाद I beg to move: Page 4, lines 25 and 26,-"or recommendation" for substitute-"recommendation or investigation" (47). SHRI Ρ. VISWAMBHARAN (Trivandrum): I beg to move: Page 4, line 6,for "after consultation with" substitute--- "on the advice of (96).

•The following Members also recor ded their votes:— AYES: Sarvashri Om Prakash Tyagi and Ram Gopal Shalwale;

NOES: Shri Ganga Reddy.

*Other amendments negatived: Nos 6, to 8, 18, 19, 21, 23, 28, 31, 38, 42, 45 46, 49 to 51, 62 to 65, 86 to 88, 95, 100, 101, 103 to 106, 113 to 115, 118, 119, 138, 143, 145 and 146. Page 4, line 7,-

"after "and" insert—after consultation with" (97).

SHRIB. P. MANDAL: I beg to move: ---

Page 4,---

for lines 6 to 10, substitute-

- "(a) the Lokpal shall be appointted from among the panel of three names in the following order:—
 - (1) one name to be given by the Chief Justice of India.
 - (2) one name to be given by the Speaker of Lok Sabha,
 - (3) one name to be given by the Comptroller and Auditor General of India." (122).

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga): I beg to move: Page 4.—

after line 12, insert-

"Provided that no person who is or had been a Minister either in the Central Government or State Government or who is holding or had held an office of the Secretary or any other Government post shall be approinted as a Lokpai or Lokavukta." (140).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 4.-

after line 12, insert-

"Provided further that no person who is or has been an active member of any political party shall be appointed as the Lokpal or a Lokayukta." (176).

ग्राध्यक्ष महोदय, भेरा निवेदन है कि क्लाज नम्बर 3 जो कि लोकपाल तथा क्रोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में है उसमें बतलाया गया है कि प्रेसीडेंट उनकी नियुक्ति किन किन लोगों से सलाह करके करेगें ।

मेंने अपने इस अमेंडमेंट के डारा यह बाहा कि इस विष्ठेयक के क्लाज नम्बर 3 में पेज 4 पर लाइन 25 ग्रौर 26 में फौर "ग्रौर रैकमेंडेशन सब्सटीच्यूट" रैकघेंडेशन ग्रौर इनवेस्टिगेशन" । मैंने यह संगोधन इस-लिए चाहा है कि यह लोकपाल तथा लोका-युक्त जोकि विभिन्न प्रधिकारियों, संस्थानों ग्रौर राज्य व केन्द्र के मंत्रियों के विरूद्ध प्रष्टाचार ग्रादि की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करेगें तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जोकि प्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों की जांच पड़ताल करेगें उनका इम्पाशियल होना तटस्थ होना परमावश्यक है।

अघ्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि तटस्थता में यदि आजकल कोई सबसे बड़ी बाघक चीज है तो यह राजनैतिक तिबारघारा के लोग हैं, पोलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जोकि साम्प्रदायिकता के आघार पर, कास्ट, क्रीड और रैलीजन इन सबको अपने सामने रखकर चलते हैं । आजकल एक नई प्रकार की साम्यप्रदायिकता दिखाई दे रही है और वह है राजनीति । अब किसी भी राजनैतिक पार्टी से यदि कोई आदमी सम्बन्ध रखता है तो वह प्रन्य राजनैतिक पार्टी की मच्छी या बुरी किसी भी बात को वह मानने को तैयार नहीं होता और उसकी आलोचना तथा बुराई करने के लिए हमेशा वह तैयार रहता है ।

इसी कारण हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रकार के नियम बनाये हैं कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी में कोई गवर्नमेंट सर्वेट भाग नहीं लेगा । गवर्नमेंट सर्वेट के किसी भी पोलिटिकल पार्टी में भाग लेने से रोकने का अद्देश्य यह है कि जितना भी सरकार का कार्य हो वह निष्पक्ष हो भीर न्यायपूर्वक हो मगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी पोलिटिकल पार्टी से बन्ध जायेगा तो वह उसके साथ रियायत अकर [श्री मोन प्रकाश त्यागी]

करेगा । ग्रगर लोकपाल या लोकापुक्त किसी भी राजनीतिक पार्टी का ऐक्टिव मेम्बर रह चुका है या है तो उसको इन पदों पर नहीं रखा जाना चाहिये ।

भी रघुवोर सिंह झास्त्री (वागपत): माननीय सदस्य किस क्लाज पर बोल रहे हैं ?

भी भोम प्रकाश त्यागीः क्लाज 3 पर।यह 3 (ए) में म्राता है उसमें लिखा है कि :

"the Lokpal shall be appointed after consultation with the Chief Justice of India and the Leader of the Opposition in the House of the People.."

उस में मैने इ जोडा है कि :

"Provided further that no person who is or has been an active member of any political party shall be appointed as the Lokpaj or a Lokayukta."

भी रघुवीर सिंह झास्त्री : यह क्लाज 4 पर प्रायेगा । इसमें यह इरेलेंबेट है। उस में मैने भी ग्रमेंडमेंट दिया हम्रा है ।

MR. SPEAKER: I will now put all the amendments to clause 3 to the vote of the House.

Amendments Nos. 47, 96, 97, 122, 149 and 176 were put and negatived.

MR. SPEAKER: Now, the quesestion is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted. Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4— (Lokpal or Lokayuktas to hold no other office).

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): I beg to move:

Page 4, omit lines 34 and 35 (66) Page 4, omit lines 38 and 39 (67). भी रघुवीर सिंह झास्त्री : "लोकपाल तथा लोकायुक्त विवेयक" की घारा 4 (ग) में वर्तमान के स्यान पर निम्नलिखित रक्षा जाय

''वह कभी किसी राजनैतिक इस्त्र का सक्रिय कार्यकर्त्तान रहाहो ।'

SHRI LOBO PRABHU: My good friend, Mr. Tyagi, has already supported my amendment that it is not proper for any one associated with a political party—and I would add, any one who is a Member of Parliament to be eligible to be Lokpal.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AF-FAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): These amendments have been rejected and clause 3 has been adopted by the House.

SHRI LOBO PRABHU: My amendments are to clause 4. I want lines 34 and 35 and 38 and 39 should be deleted because there should be 87 absolute bar on anyone who is associated with a political Party or any one who is a Member of Parliament. We have heard of defeated Members of Parliament appointed to different posts. It is something more than that that an acting Member should be appointed to this post. A Member of Parliament has a duty. He has been elected for a specific purpose. I press both my amendments for the deletion of these two sub-clauses allowing exemption to a member of a political party and to a Member of Parliament.

धी झोम प्रकाश स्थागी: में कहना चाहता हूं कि कोई ग्रादमी ग्रगर किसी पोलिटिकल पार्टी का ऐक्टिव मेस्बर है या रह चुका है तो उससे किसी भी जांच के न्यायपूर्वक होने को ग्राष्ता नहीं की जा सकती । मेरी तो ऐसी ही मान्यता है । सरकार ने इसी बात को दृष्टि में रखते हुए ग्रपने सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबन्ध लगाया है कि कोई सरकारी कर्मबारी किसी पोलिटिकल पार्टी से

सम्बन्ध नहीं रखेगा। यही नहीं कि वह पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर नहीं रहेगा बल्कि वह नडाईरेक्टली भी किसी ोलि-टिकल पार्टी से सम्बन नहीं रखेगा । ऐसी स्थिति में जो लोकपाल ग्राप नियक्ति करने जा रहे हैं यदि वह ऐसा भ्रादमी होगा जो पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर रहा हो या किसी सरकारी कमिशन में रहा हो, सरकारी उद्योगों में रहा हो, तो वह ग्रपनी पार्टी के ग्राधार पर एटमास्फिग्रर किएट करेगा। मै इन्स्टिट्यु शन का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन रांची केहेवी इंजीनियरिंग कार-पोरेशन में श्री मालवीय नियुक्ति हुए । वहां जाते ही उन्होंने इन्टक का जोर शुरु किया ग्रीर वहां की लेबर में बडी गडबडी पैदा कर दी ।

सलिए ग्रगर कोई भी ग्रादमी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्धित रह चुका है, तो उसको लोकपाल या लोकायुक्त के पद पर नियुक्त करना खतरे से खाली नहीं है। मैं इस ग्रमेंडमेंट को पेश करता हूं ग्रीर ग्राशा करता हूं कि मंत्री महोदय स पर गम्भीरता से विचार करेंगे गगर वह इस विधेयक की सफझता चाहते हैं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मेंने ग्राना सशोधन इसलिए रखा है कि भ्राज जब कभी हम देश में निष्पक्ष व्यक्ति ढूंड़ने लगते हैं तो ग्राम तौर पर एक शर्तं यह रखी जाती है कि वह व्यक्ति साम्प्रदायिक नहीं ोना चाहिये, किसी सम्प्रदाय विशोष में विश्वास करने वाला नहीं होना चाहिए । लेकिन हमारे राजनीतिक जीवन में इतनी खांचातानी हो गई है कि जितनी दलीय भावना सम्प्रदायों में है उससे कम राजनीतिक दलों में ग्रापस में नहीं है । ग्राप जिसको लोकपाल नियुक्त वरेंगे वह कम से कम 55 ये 60 वर्षं की स्रायुका तो होगा। जो ग्रादमी 55 या 60 वर्ष तक किसी दल के साथ रहा है, दल के साथ उसका लगाव रहा है, दल के लोगो के साथ उसकी मित्रता रही है, उसके भन्दर उनके प्रति सदभावना हैं ग्रौर दूसरे दलों के प्रति उसके हदय में दूसरी प्रकार के भाव हैं, भगर ऐसे व्यक्ति को नियक्त किया जायेगा. तो उसका झकाब ग्रपने दल की श्रीर होगा। कोई भी छोटी या बढी इक्य हो, छोटी या बडी नियक्ति हो, जिस दल के हाथ में नियुक्ति करने का ग्रधिकार होता है वह सोचता है कि उससे सरकारी दल का लाभ होने वाला है या नहीं । जो भी लोक पाल को नियक्त करेगा वह यह देखकर नियुक्ति करेगा कि इससे सरकारी दल को हानि हो रही है या लाभ हो रहा∉ है-। इससे लोकपाल ग्रीर लोका-यक्त की निष्पक्षता पर ग्रांच ग्रायेगी । इसलिए में कहना चाहता हूं कि जब झाप लोकपाल नियक्ति कर रहे हैं तो लोकपाल की नियक्ति कराइये दलपाल की नियक्ति न कराइये। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो इस विधेयक के पीछे जो भावना है वह सारी नण्ट हो जाऐगी।

मेरा मनुरोध यह है कि इस में माप यह म्रवभ्य रक्खें कि वही व्यक्ति लोकपाल नियुक्त किया जाये जिसका कभी किसी दल के साथ कोई सम्बन्ध न रहा हो, म्रगर माप चाहते हैं कि इस पद पर निष्पक्ष व्यक्ति रखा जाये। जिस प्रकार म्राप म्रसा-म्प्रदायिक व्यक्ति कहते हैं उसी प्रकार यहां यह होना चाहिये कि जो भी नियुष्ति म्राप करें वह पोलिटिकल नियुक्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री विद्या चरण शुक्सः ग्रघ्यक्ष महोदय जो भावनायें माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं उनसे मैं पूर्ण सहमत हूं । सवाल यह है कि इस में किस प्रकार का प्रावधान करना चाहिये जिस से यह भावनायें पूरी हो सर्के इस के लिए हम लोगों ने प्रावधान में कहा है कि जिस व्यक्ति को इस में रखना हो उस को केवल प्रधान मंत्री की तरफ से न रखा जाय बरिक जो हमारे विरोधी दल के नेता

धी विज्ञा चरल भुक्ल]

हैं, और यदि एक नेतान हो तो समस्त विरोवी दल के लोग एक व्यक्त को डांट लें, उससे परामर्श करके रखा जाये । इसके साथ साथ हमा चोफ जस्टिस से भी पूछा खात्र झौर उसे पूछने के बार लोकपाल को नियुका किया जाय । इस का मतलब यह होता है कि ऐसा व्यक्ति लिया जायेगा जिस के बारे मे लगभग सर्वसम रिहो ।

13.03 hrs.

यदि हम किसी तरह का उस में बन्धन लगाना चाहें कि वह राजनी तेक का क्तर हा हो प्रार उसको चाहे सभी जोग पसन्द करते हों, चीफ जस्टिस मी सन्द करें, विरोबी दल के नेता भी पसन्द करें, राजनी तिक दल जो केन्द्र में है प्रार प्रान्त में है, वह भी पसन्द करें, तो बूं कि वह दो तीन साल या दस बीस साल तक किसी राजनी तेक दल में रह चुका है लेकिन हर तरह से योग्य है भीर उनको इस वास्त ग्रयोग्य ठहरा दिया जाए कि वह किमी राजनी तेक दल आ सदस्य रहा है, तो मैं समनता हूं यह ठीक नहीं होगा। इस तगह का कोई भी संगोधन स्वोकार करने में मैं प्रत व हूं।

SHRI LOBO PRABHU: What about "Member of Parliament'? The hon. Minister has not replied to my question. He has not replied to my objection that a Member of Parliament should not be eligible for appointment as Lokpal.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We have provided that if a Member of Parliament is appointed, he will vacate his seat.

SHRI LOBO PRABHU: He is bound to do that.

SHRT S M BANERJEE (Kanpur): Why should he object? We are going to recommend his name;

MR. SPEAKER: I shall now put amendments Nos. 66, 67, and 195 to vote. Amendments Nos. 66, 69 and 195 were put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That cause 4 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. SPEAKER: We shall take up clause 5 after lunch.

13.03 hrs.

[SHRI M. B. RANA in the Chair.]

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL -- contd.

Clause 5.—(Term of office and other conditions of service of Lokpal and Lokayukta).

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move:

Page 5 lines 35, and 36,—after "Government" insert 'or private" (41).

Page 5, line 36, add at the end---"or companies or societies owned or controlled by big business houses (143).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 5, line 36,—add at the end— "or in companies or societies owned by big business houses". (178).

MR. CHAIRMAN: We have exhausted the time allotted.

I shall put to vote amendments Nos. 41, 148 and 178.

Amendments Nos. 41, 148 and 178 were put and negatived.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

461 Lokpal and SRAVANA 29, 1891 (SAKA) Lokayuktas Bill 462

ł

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6- (Removal of Lokpal or Lokayukta).

MR. CHAIRMAN: There are amendments, 15, 48, 180, 181 and 182.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani): I beg to move:

Page 6, line 33,—for "by each House of Parliament", substitute "by the House of People" (15).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 6, lines 22 and 23,-

for "on no other ground" substitute "malpractice" (48).

Page 6, line 22,-

after "misbehaviour" insert. "misconduct" (181).

Page 6, lines 22 and 23,-

omit and on no other ground." (182).

श्वी शिव चन्द्र झा: सभापति महोदय, चलाज 6(3) में लोकपाल ग्रीर लोकायुक्त को उन क पद से हटाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि संसद् के दोनों सदनों के बहुमा दारा गष्ट्रपति को इस ग्राधय का एड्रेस दिये जाने १२ उन्हें हटाथा जा सकेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकपाल ग्रीर लोकायुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्लाज 3 में यह व्यवस्था की गई है कि इस विषय में लोक सभा में ग्रापोजी-घन के नेता के साथ परामर्श किया जायेगा। उस क्लाज मे राज्य सभा का कोई उल्लेख मईंहे । मेरा कहना यह है कि बब सोकपाल भौर लोकायुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में केवल लोक समा का जिक किया गया है, तो फिर उन्हें बर्खास्त करने के मामले में राज्य समा को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है । जब लोक समा उन्हें बहाल करती है, तो उसी को यह पावर होनी चाहिए कि वह उन्हें हटा सके । अपने संशोधन संख्या 15 द्वारा मैं यह चाहता हूं कि संसद् के दोनों सदनों के बजाये केवल लोक सभा द्वारा बहुमत से भेजे गये एड्रेस के आधार पर लोकपाल या सोकायुक्त को हटाया जा सके।

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): I move my amendment No. 180:

Page 6,-

for lines 22 and 23, substitute— "President on the ground of misbehaviour and incapacity, and that he has allowed himself to be influenced by any Minister in taking decisions with regard to any matter under investigation by him, and on no other ground." (180).

The basic point is that if the Lokpal allows himself to be influenced by a Minister, that should be a ground for his removal. It should not be necessary to have a two-thirds majority for his removal; a simple majority should be good enough. Instead of both the Houses concurring in it, if either of the Houses decides that the Lokpal should be removed by a simple majority, he should be removable.

भी भोम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय मैं एक छोटा सा प्रश्न पूत्रांगा थोडा शंका समाधान के लिए। इ.क्ष क्लाउ 6 में ग्राप ने कहा है :

"Subject to the provisions of article 311 of the Constitution, the Lokpal or a Lokayukta may be removed from his office by the President on the ground of misbehaviour or incapacity and on no other ground.".

[श्री स्रोम प्रकाश त्यागी]

े में पूछना चाहता हं कि मिसविहेवियर, इनकै-पेसिटी यह तो ठीक है लेकिन ग्रगर करप्ट है वह तो ? ग्राप यह कहते हैं कि नो भ्रदर गाउन्ड, यह जो पीछे जोड देते हैं. यह गलत है । कोई दूसरी भी शिकायत हो सकती है. इसरे ग्राउन्ड भी हो सकते हैं। ग्राप ने सिर्फ दो चीजों को ले लिया है मिसबिहेवियर ग्रौर इनकैपेसिटी लेकिन ग्रगर वह करप्ट हैं या इस प्रकार की भाईबन्दी की बात उसने की है, द्निया भर की बातें हैं, ग्रनेक बातें हो सकती हैं, तो वैसी हालत में न तो भौर ग्राउन्ड किसी के लिए भी बाइंडिंग हो जाएगा। इस प्रकार के लोकपाल ग्रौर लोकायक्त को इतना एबव ग्राप रस देंगे कि जिस से कोई उस को हटा न सके तो कल ग्राप के लिए मुक्किल हो जायगी । इसलिए नो भ्रदर ग्राउन्ड को ग्राप हटा दीजिए।

SHRI S. M. BANERJEE: I just want to say a word....

MR. CHAIRMAN: The hon. Member does not have any amendment.

SHRI S. M. BANERJEE: I want to support his amendment.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has understood the point. Now, let him reply.

SHRI S. M. BANERJEE: I am in your hands,

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: If hon. Members would carefully see the clause they will see that misbehaviour on the part of the Lokpal would embrace all these questions that hon. Members have in mind. For instance, getting influenced by anybody including a Minister or being corrupt tantamounts to misbehaviour. As a matter of fact, we have used the language of article 124(4) of the Constitution, and since we are equating the Lokpal with the judges of the Supreme Court, whatever grounds have been mentioned for the removal of Supreme Court judges have been mentioned for the removal of the Lokpal also. I would, therefore, request hon. Members not to press their amendmens as far as this particular matter is concerned.

Shri Shiva Chandra Jha wants that only the lower House should have the authority to proceed against the Lokpal. Here, again, I would invite his attention to the Constitution where removal of the Supreme Court judge requires an address to be presented by both Houses of Parliament and not only the lower House. In this case also, we have kept the provision that both Houses of Parliament should be consulted, so that both Houses are kept in the picture whenever the necessity for removing the Lokpal might arise.

SHRI S. S. KOTHARI: It should be by a simple majority.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Therefore, I would not be in a position to accept any of these amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendments to clause 6 to vote.

Amendments Nos. 15, 48 & 180 to 182 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

clause 7— (Matters which may be investigated by Lokpal or Lokayukta.)

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): I beg to move:

Page 6, line 40, after 'Minister' insert—'including the Prime Minister'. (24)

SHRI P. VISWAMBHARAM: I beg to move:

Page 6, line 40, add at the end 'A Member of Parliament'. (98). 465 Lokpal and SRAVANA 29, 1891 (SAKA) Lokayuktas Bill 466

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move:

Page 7, after line 28, insert: "(5) Subject to the provisions of this Act, the Lokpal may investigate in the manner to be prescribed under the rules the assets held by Ministers and Secretaries to find out if the assets so held are disproportionate to the lawful income of Ministers and Secretaries". (149).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move :

Page 6, after line 39, insert "(i) the Prime Minister or the Deputy Prime Minister". (183)

SHRI S. S. KOTHARI: I beg to move:

Page 7, after line 28, insert-"(5). The Lokpal may investigate

the assets held by Ministers and Secretaries to ascertain if the assets so held are disproportionate to the lawful income of the Ministers or Secretaries.". (188).

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट कहना है, मेरा जो संशोधन है उसकी 28वीं लाइन के बाद एक नया पैरा हम जोड़ना चाहते हैं जिस का ग्राशय यही है कि जो मिनिस्टर या सेकेटरी होते हैं उस समय जो उन की सम्पत्ति का व्यौरा होता है ग्रौर ग्रागे चल कर बहुत से लोग बहुत सा घन अजित कर लेते हैतो में बहुत ज्यादा का फर्कहों तो इस संशोधन के मताबिक लोकपाल को यह ग्रयिकार होना चाहिए कि वह उस में दखल दे,उस की जांच करे ग्रौर ग्रपनी सम्मति दे. इसलिए इस को मैं इस में जोड़ना चाहता हं । भ्राप जानते हैं हमारे बिहार में कुछ पराने मत्रियों पर मुकदमें भी चल रहे हैं कि पहले उन की कितनी सम्पति थी ग्रौर बाद को उन्होंने कित्तनी सम्पत्ति र्क्राजत कर ली । यह बात सब जगह खुली हई है । इसलिए में समझता हं कि इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई हिचक मन्त्री महोदय को नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रपर यह बात साफ हो जाय कि बहुत फर्क है उन की मूल सम्पत्ति और मिनिस्टर और सेक्रेटरी होने के बाद जो उन की सम्पत्ति हुई दोनों में तो उस की जांच करने का श्रधिकार लोकपाल को होना चाहिए जिससे जो गलत तरीके से धन श्रजित किया जा रहा है उस को रोका जाय और साथ ही साथ उन के खिलाफ कार्यवाही की जाय । इस में कोई एसा बात नहीं है जिसे मंत्री महोदय स्वीकार न करें ।

SHRI S. S. KOTHARI: When corruption is rampant, it is not possible generally to catch the offenders redhanded. But assets are something which could be ascertained with definiteness. If it is found that the assets of a secretary or a Minister are disproportionate to his income, he can easily be apprehended and it should be within the ambit of the Lorpai's powers to investigate into the matter, and wherever there is any suspicion he should go into the details and he can also take the assistance of experts and others. If the assets are found to be disproportionate, he can make a recommendation that necessary action should be taken. He can call upon the person concerned to explain how he acquired those assets, and if he cannot explain them satisfactorily, action can be taken. Actually, it is a lacuna which would be removed and I think the hon. Minister should accept this amendment.

SHRI P. VISWAMBHARAM: Clause 7(1) says:

Subject to the provisions of this Act the Lokpal may investigate any action which is taken by, or with the general or specific approval of-

(i) a Minister or a Secretary; or.

My amendment seeks to include 'Member of Parliament' also in this clause. It is not fair on our part to exclude Members of Parliament from

[Shri P. Viswambharam]

the purview of this Bill. If we ourselves do not submit to be scrutiny of the Lokpal, then we have no moral right to pass this Bill. Therefore, I have moved this amendment. Since this is going to be a model legislation for the State_S also, we should set up an example to the States. Therefore, I would urge the hon. Minister to accept my amendment.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I would invite the attention of hon. Members, particularly Shri Ramavatar Shastri and Shri S. S. Kothari to clause 2 (b) which gives the definition of the term 'allegation'. If the Bill did not contain any provision to cover the contingency that the hon. Members have in mind, I would have had no hestitation to accept the amendment, but according to this definition of allegation, such matters are completely covered under this Bill. The Lokpal can definitely look into the disproportionate assets of secretaries and Ministers under this particular power that has been given. Further, under his own suo motu nowe s which have been given to him under clause 11 (1) and clause 11 (2). the can call for the statement. If such statements are not available on record or anywhere else, from the secretaries and Ministers and look into into the those things and also go matter. So, all these matters which the hon. Members have in their mind are already covered under the existing provisions, and therefore, it will not be necessary to accept any of the amendments. (Interruption). I said I would have been happy to sccept it if it was not the e. It is already there and we should not make such an important pice of legislation cumbersome and repetitive. Therefore, I hope the hon. Members will not press the amendment because it is already there. It already finds a place there,

Regarding Members of Parliament, this matter was very deeply considered. You. Sir, were the Chairman of the Joint Committee, and we considered this matter quite deeply in the Joint Committee, and it was ultimately found that it would not be proper and it will not fit in the scheme of things if Members of Parliament were to be included in the purview of Lokpal and Lokayukta. Therefore, we took a decision not to include Members of Parliament in the purview of Lokpal. Therefore, I am unable to accept that amendment also.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendments to clause 7 to the vote.

Amendments Nos. 24, 98 149, 183 & 185 were put and negatived

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8—(Matters not subject to investigation.)

SHRI LOBO PRABHU: I move:

Page 8, omit lines 8 to 10. (75) SHRI N. K. P. SALVE: I move:

Page 7, for lines 36 to 40, substitute

"Provided that a remedy before the High Court or the Supreme Court to issue directions, orders or writs under article 226 or article 139 respectively of the Constitution in respect of any grievance will not be deemed to be a remedy within the meaning of item (b) of sub-section (1):

Provided further that the Lokpal or Lokayukta may conduct an investigation notwithstanding that the complaint had or has such a remedy if the Lokpal or as the case may be the Lokayukta is satisfied that such person could not or cannot for "ufficient cause have recourse to such remedy:

Provided further that in case the Tribunal or the court of law, as the case may be, before whom remedy against an action is sought makes an Order in favour

469 Lokpal and SRAVANA 29, 1891 (SAKA) Lokayuktas Bill 470

of the complainant and the tribunal or the court of law, as the case may be, making such order in favour of the complaint is not competent to proceed against, the public servant on whose action they have made such order. a complaint against such action. shall notwithstanding caluse (b) of sub-section (1), be entertained by the Lokpal or Lokayukta if the same, prima facie, indicates either mala fide, corrupt, perverse grossly negligent act on the part of a public servant involving gross abuse of his powers and authority." (89).

MR. CHAIRMAN: Shri Lobo Prabhu. Just one minute. We have already exceeded the time.

SHRI LOBO PRABHU: This is raimportant amendment. ther an I would not take one extra minute. Now in this amendment, I have which said that the provision exempts from the jurisdiction of Lokpal mentioned in clause (k), subclause (iv) should be deleted.

I would like to refer the Minister to clause (k), sub-clause (iv) of clause 2. This clause includes an officer employed in any local authority, in any corporation, any Government company, any society. (Interruption). The measure of corruption is as high in these corporation and local bodies. I would like to know why, when you are concerned with corruption, you are exempting an area which is so heavy, so rich, with corruption.

I will ask the Minister another question. If it was not the intention to include these classes under the jurisdiction of the Lokpal, what is the purpose of this clause (k), subclause (iv)? There was no necessity at all to designate these officers: either vou completely delete this class of officials or place them under the jurisdiction of the Lokpal.

I need not say the Minister must be very tired already of rejecting the amendments, but I am not tired of pressing my amendments. Amendments are a legitimate part of the pro-

cess of legislation. Is the Minister thinks that no amendments should be accepted, I would like him sometimes to wonder why he has not objected to the very structure of our procedure here, because, to turn down every amendment from every Member does not do credit to this House. I may add that legislation is a most important part of the work of this House. If you do not take the co-operation of the Opposition, if you think what has been put to you by your officers is the last word, you are making a very fatal mistake in respect of the functions of this House.

SHRI- N. K. P. SALVE: The amendment which I have moved seeks to provide two provisos n addition to the one which is already there in the Bill. The entire purpose of the two provisos is to delete the unintended effect which might come as a result of drafting. It is stated in the Bill that no complaint can be made of a grievance if the complainant has any remedy by way of proceedings in a court of law. My first proviso seeks to make it clear that even if there is a remedy open to the complainant by way of a writ petition in a High Court, it should be open to the person to go to the Lokpal or Lokayukta instead of a writ petition because of the difficulties involved in filing 2 writ. The subject-matter in many cases would be almost the same. Yet, if a remedy is available to a person by way of a writ petition, he should not be compelled to go to the High Court by way of a writ, even though that right is available to him; it should be open to him to go to the Lokpal or Lokayukta instead of court.

SHRI SRINIBAS MISRA: Nobody can compel him to go to the court.

SHRI N. K. P. SALVE: Suppose a remady by way of a writ is available. They may not entertain the grienvance or complaint on the ground that a remedy is available. It is likely to happen. At least, that is my view of the matter.

[Shri N. K. P. Salve]

Secondly, we have left judiciary entirely out of the purview of this Bill. Now we are likely to leave out a very important section of the executive; I am worried about the Income-Tax Department Sales Tax Department. Customs and Excise. In regard to income-tax there is remedy provided in the tribunal and in the High Court: High Court is the last court, so far as questions of law are concerned and the tribunal is the last one, so far as question of facts are concerned. It is more than likelv that several questions will arise in respect of which one cannot go to the tribunal or the High Court and there is no remedy available before an aggrieved party. Now we have defined "grievance" as undue hardship and injustice. The very same definition comes also under "allegation"-undue harm or undue hardship to any person concerned. If there is any undue harm or undue hardship to any party, he will still not be able to go to the Lokpal and the income-tax officer will go on merrily doing whatever he wants. We are collecting Rs. 2,200 crores by way of direct and indirect taxes. So, it is absolutely imperative that the Lokpal and the Lokavukta must have jurisdiction over those people who are collecting these direct and indirect taxes. If, for any reason, the Home Minister considers that officers of income-tax, sales-tax, customs and excise are already covered by clause 8 (1), I would request him to consider one point. We have been having ho many litigations on account of improper drafting because the intentions of the legislature are not brought out to the statute book in a proper and apt manner. Therefore, in order to avoid any such unnecessarv litigation, if what I am saying is already there in the statute book, and if it is not there, to rope in all those people who are responsible for collecting direct and indirect taxes, these two provisions must also be added.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The amendment moved by Shri Salve has been very carefully considered by us. We wanted to find out whether we can improve upon this scheme. But, as far as his fears are concerned. we found that they are already covered by the provisions of this Bill. As he himself was stated, whereas grievances are concerned, there are remedies otherwise available by a writ petition or by going to a tribunal. The applicant can go and agitate the matter before them. But, as far as the allegations are concerned, they come under the purview of this Bill. So, if there is any allegation that an assessee wants to make in regard to any tax matter against the Income-tax Officer or the Assistant Commssioner of Income-tax or the sales-tax Officer. he can still go to the Lokayukta: there is no bar. If he has a crievance of over-assessment, or wrong assessment against the Income-tax Officer, he can certainly appeal to the superior authority from the Incometax Officer he can go to the Assistant Commissioner from the Commissioner of Income-tax to the Tribunal. He can also go by a writ petition to the High Court.

Therefore, I do not think it would be possible for us to include all those things and widen the area of the Lokpal and the Lokayukta in such a manner that 't becomes completely impossible tc work Therefore, wherever there is a remedy available aganist grievances, we have not included it here but as far as allegations are concerned, all allegations are included in this and anybody who has any allegation against any member who is working for the Union Government can come up to the Lokpal and agitate the matter before the Lokpal or the Lokayukta as the case may be.

Shri Lobo Prabhu should not get disheartened if his amendments are not found acceptable by us. It is not that we do not want to accept any amendments. Shri Lobo Prabhu should know that in the Joint Committee dozens and dozens of amend-

ments moved by hon. Members belonging to the Opposition parties were accepted by us to this Bill and we are thankful to them for having gone so deeply into the matter and suggested such useful amendments. Having done that, it is not right for any hon. Member to say that we reject amendments because we are completely closed to accepting amendmens from hon. Members. Wherever any amendment is found suitable and useful. we would definitely accept it. Shri Lobo Prabhu has taken a lot of pains in moving his amendments and some of his amendments are useful; but if they are already covered under the provisions of the Bill, I am not in a position to accept them.

His amendment here says that persons belonging to the public sector undertakings or the Corporation and other things in the Union territory should be covered by it. They are covered as far as allegations go but they are not covered as far as grievances are concerned. If there is a tender awarded by a public sector undertaking and there is some difficulty about the tender, persons who have not been awarded the tender can go to the higher authority; they can come to the Government and can even go to the court and challenge that kind of discrimination on various grounds that are provided for in the laws and in the Constitution; but if there is any allegation against any of these people which Shri Lobo Prabhu has in mind, that is already covered by this Bill for the allegations of the categories which Shri Loo Prabhu has indicated are already covered under the Bill. Therefore the intention that he has in mind to fight corruption or to discourage such tendencies among public servants in Union territories and in the public sector organisations is already covered under this and I do not think it is necessary for me to accept any of these amendments.

SHRI N. K. P. SALVE: In view of the explanation of the Home Minister I seek leave of the House to withdraw the amendment.

SHRI LOBO PRABHU: I also wish to withdraw my amendment.

MR. CHAIRMAN: Have the hon. Members the permission of the House to withdraw their amendments?

- Amendments Nos. 75 & 89 were, by leave, withdrawn.
 - MR. CHAIRMAN: The question is: "That clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill

Clause 9—(Provisions relating to complaints).

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Sir, I move:

Page 8, line 35,---

after "allegation", insert-

"anonymous or" (17)

SHRI SRINIBAS MISRA: Sir, I move:

Page 9, line 7,-

for "place" substitute "institution" (52)

Page 9, line 10,-

for "place' substitute "institute" (53)

Then, under rule 79 I may be permitted to move amendment No. 54 in a modified form. It was submitted in one form but now I want to make some verbal changes. I move:

Page 9, line 10,---

add at the end .---

"and the Lokpal or Lokayukta as the case may be, may, if satisfied that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of 3ub-section (2)". (54)

SHRI B. P. MANDAL: Sir, I move:

Page 9, after line 10, insert—"Provided that no stamp or fee of any type shall be charged for filing any complaint." (132). SHRI OM PRAKASH TYAGI: Sir, I møve:

Page 9,---

after line 10, insert—"Provided that no stamp duty or fee of any type shall be charged for filing any complaint." (138).

SHRI SRINIBAS MISRA: My amendments Nos 52 and 53 are almost the same amendments. According to the previous provision in this Bill, persons who are in custody will write the letter to the Lokpal and the Lokayukta and that letter will be forwarded by the person having their custody. It was strange that originally the drafting was:—

"Notwithstanding anything contained in any other enactment, any letter written to the Lokpal or Lokayukta by a person in police custody or in a jail or in any asylum or any place for insane persons."

Previously, was "receptacle" in place of "place", as if our insane persons were kept inside a vat. The Joint Committee changed it to 'place''. My submission is that that is not appropriate. Perhaps the hon. Minister will concede that there are benches in parks and many insane and mad persons go and live there. Will it be necessary for the keeper of the park to forward his letters? So, I have tried to suggest that in place of "place", the word "institution" should be substituted. The proper word is 'institution'. Wherever insane persons are kept under custody or in the care of somebody, there is an institution, not a place like river bank or park where some insane persons collect and there is a PWD officer-incharge or somebody. It is not that. It should be an institution.

Then, my amendment No. 54 in modified form is like this. On P. 9, line 10, add at the end, "and the Lokpal or Lokayukta as the case may be may, if satisfied that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2)". What I mean to suggest is that whenever such a person writes a letter, it shall be forwarded and whenever the-Lokpal or Lokayukta thinks that he can act upon that letter, he will treat it as a complaint.

It is a very simple and clear amendment and, I hope the Government will accept it.

श्वी शिव चन्द्र झा: समापति महोदय, मेरा संशोधन क्लाज 9 (बी) में है:

Page 8, line 35,-

after "allegation", insert—"an-. onymous or"

शब्द "एलिगेशन" के बाद म शब्द "एनानिमस श्रौर" जुड़वाना चाहता हूं । लोकपाल श्रौर लोकायुक्त के सामने जो शिकायत की जायेगी, कौन आदमी शिकायत कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, किस तरह से लोकपाल श्रौर लोकायुक्त के ढारा जांच की जायेगी, उसके मुताल्लिक यह है । जो शिकायत करने का तरीका रखा गया है उसमें है:

"Every complaint shall be made in such form and shall be accompanied by such affidavits.... as may be prescribed."

तो यह तरीका ठीक नहीं है । बहुत से लोग समाज में सराबियों को जानते हैं, बड़े प्रफसरों ग्रीर मिनिस्टरों की सराबियों को जानते हैं लेकिन उनकी कहने की हिम्मत नहीं होती है । ग्रगर ग्राप इसको इसी तरह से रखते हैं तो शायद कोई भी शिकायत सामने न ग्राये । इसीलिए मैं चाहता हूं कि एनानिमस शब्द भी इसमें जोड़ दिया जाये, ग्रगर कोई गुप्त नाम से भी लोकपाल, लोकायुक्त को शिकायत कर देता है तो वे उसकी जांच कर लें कि प्राइमा फैसी केस बनता है ग्रीर ग्रगर बनता है तो ग्रागे उसकी जांच होनी चाहिए । इस रास्ते को मी ग्रस्तियार किया जाना चाहिए । यदि ग्राप इसी बात को रसते

हैं कि सटिफाइड, एफिडेविट लगाये तो फिर हो सकता है कि जितनी शिकायतें मानी बाहिएं उसमें से 5 परसेन्ट ही आयें भौर 95 परसेन्ट शिकायते वसे ही रह जाय । भाज दिल्ली में सभी लोग जानते हैं कि सिन्डीकेट की वजह से कितनी खराबियां हो रही हैं लेकिन किसी की सिन्डीकेट के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। इस लोकसभा के ग्रन्दर ही जो सदस्य हैं उनके दिल में रहता है, वे जानते हैं कि फला मिनिस्टर खराब काम करता है. उसके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए लेकिन एफिडेविट लगाकर वह देना चाहते नहीं हैं। इसीलिए मैंने एनोनिमस का रास्ता रखा है । इससे ग्रापका काम ज्यादा ग्राच्या चलेगा. ज्यादा शिकायते सामने ग्रायेंगी ग्रीर उस ग्रादमी के लिए धबराने की भी जरूरत नहीं होगी। इससे भ्रापके इस बिल का मकसद पूरा हो जायेगा । इसीलिए मैं जब्द एनानिमस को इसमें जड-बाना चाहता हं

श्वी श्रोम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि लोकपाल म्रौर लोकायुक्त को कम्पलेन्ट करने का तरीका बहत सरल और सीधा होना चाहिए जिससे जिसको जो भी शिकायत करनी हो वह आसानी से कर सके । बहुघा देखा गया है कि जनता में किसी को कोई शिकायत हो तो वह उसके खिलाफ कोर्ट में जाये ग्रीर वहां शिकायत करे ग्रौर फिर उसमें यह हो जाता है कि इतने का स्टैम्प हो, फलां कागज हो इत्यादि । गरीब ग्रादमियों के णस स्टैम्प के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसमें यह भा जाना चाहिए कि उसमें स्टैम्प की ग्रावश्यकता नहीं पडेंगी, कम्प्लेन्ट सीधी भीर सरल भाषा में की जा सकती है । मेरी प्रार्थना है मंत्री महोदय इसको स्वीकार करने की ज़पा करें।

भी बि॰ घ॰ मंडल : समापति जी, मेरे पूर्व वक्ता ने मेरे कार्य को हल्का कर दिया है। मेरा संशोधन इस प्रकार है :

Page 9,-

after line 10, insert—"Provided that no stamp or fee of any type shall be charged for filing any complaint".

माज गरीब म्रादमी को न्याय नहीं मिलता है । म्रदालत का रुख म्रमीर म्रादमियों के पक्ष में होता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम लोकपाल ग्रीर लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन को ग्रीर प्रवालतों की तरह नहीं बनाना चाहिये । इसीलिये स्पेसिफकली हम चाहते हैं कि कोई स्टाम्प या किसी किस्म की फीस न लगे । माननीय त्यागी जी ने भी यही बात कही है, मैं भी यही कहना चाहता हूं, ग्रीर आशा है कि मंत्री जी इस को भी मान लेंगे ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : [समापति जी, जहां तक माननीय शिव निवद झा का संशोधन हैं वह चाहते हैं कि गुमनाम तरह से जो शिकायत म्राये उस को भी लोकपाल मन्जर करे । इस विघेयक में जो हम प्राविघान कर रहे हैं उस में ऐफीडेविट लगायेगा जो शिकायत करना चाहता है । क्यों कि बिना इस के यदि कोई कमप्लेन्ट करेगा तो काफी काम बढ जायेगा जिस को लोकपाल ग्रौर लोकायुक्त नहीं कर पायेंगे । इतलिये ऐफीडेविट लगाना जरूरी है । ग्रौर जब ऐफीडेविट की बात ग्रा गयी तो फिर गुमनाम शिकायत मन्जर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी एक प्राविधान है इस बिल में जिस की तरफ माननीय सदस्यों का व्यान दिलाना चाहता हं, भौर वह यह है कि लोकपाल को इस . बात का ग्रधिकार दिया दुग्रा है कि वह स्वयं हो कर बिना किसी शिकायत के भी किसी मामले की जांच पडताल कर सकते हैं। इस के लिये उन को कोई शिकायत की झावश्य-कता नहीं है। बिना शिकायत के अपर उन को संतोष हो जाये कि जांच करनी है

[श्री विद्याचरण मुक्ल]

तो बह जांच कर सकते हैं। ग्रौर इस तरह की व्यवस्था होने के कारण जो चीज माननीय सदस्य के मन में है कि लोकपाल को अधिकार होना चाहिए, वह उन के अधिकार में ग्रा जाता है, ग्रौर जब चाहे लोकपाल स्वेच्छा से किसी भी मामले की जांच पड़ताल खुद कर सकते हैं चाहे ऐफीडेविट हो या न हो, कोई गुमनाम पत्र हो या न हो, जब चाहेगा अपने ग्रधिकार का उपयोग करके इस तरह की कार्यवाही कर सकते हैं।

जहां तक माननीय मंडल, माननीय रयागी ग्रौर माननीय श्री निवास मिश्र जी के संशोधनों का सवाल है. मैं समझता हं कि जो चन्होंने कही हैं वह काफी ठीक बात है कि यदि कोई ग्रादमी जेल से या दूसरी जगह से पत्र भेजे तो उस में इस तरह की कार्यवाही करना स्टाम्प लगाना मुझ्किल होगा, ग्रौर हो सकता है कि मपनी तरफ से वह कार्यवाही करने में उस को कठिनाई हो । इसलिये में ग्राप के संगोधनों को स्वीकार कर सकता डं। पर जो संशोधन संशोधित रूप में माननीय मिश्र जी ने दिया है वह संशोधन ऐसा है जिस को मैं स्वीकार कर सकता हूं । इसलिये माननीय श्रीनिवास मिश्र जी का जो 54 नम्बर का संशोधन है उस को मैं स्वीकार करूंगा (व्यवधान) हम ने इस को ≪लेस किया था, लेकिन ग्रब ग्रा२ इंस्टीट्-य शन शब्द वाहते हैं। साननीय मिश्रा जी के संशोधन संख्या 52, 53 के बारे में मैं ग्राप को ग्रभी बताऊंगा।

संशोधित फार्म में जो संशोधन माननीय "मिश्रा जी ने पेश किया है वह संशोधित "फार्म मुझे मन्जूर है। उस में वही चीउ है जो माननीय त्यागी जी ग्रौर माननीय मंडल जी चाहते हैं। ग्रौर मै उम्मीद करता हूं कि चूंकि माननीय श्रीनिवास मिश्रा जी का संशोधन स्वीकार कर लिया है इसलिये ब्दोनों सदस्यगण ग्रपने प्रपने संशोधन, जिनका वैक मतलब वही है, वापस ले लेंगे। माननीय मिश्रा जी के जो 52 ग्रौर ग्रौर 53 नम्बर के संशोधन हैं उस में वह चाहते हैं कि 'प्लेस' की जगह 'इंस्टीट्यूशन' किया जाये ।

सुभापति जी, ग्राप को याद होगा कि जब प्र वर्र समिति में यह मामला चल रहा या तो काफी बातचीत इस पर हुई थी ग्रौर प्रवर समिति में ही हम ने 'रिसेप्टिकल' को बदल कर 'प्लेस' किया था। ग्रौर भव फिर माननीय सदस्य चाहते हैं कि 'प्लेस' बदल कर 'इंस्टीट्यू रान' किया जाये । मेरी प्रार्थना है कि 'प्लेस' में 'इंस्टीट्यू रान ' शामिल है । 'प्लेस' में ऐसा नहीं है कि 'इंस्टीट्यू रान' ऐक्सकलूडड है । ग्रौर चूंकि प्लेस वाइड राब्द है, उस में ये सब चीजें प्राती हैं, ग्रौर जो माननीय सदस्य का मतलब है वह इस में शामिल है । इसलिये मैं चाहूंगा कि संशोधन संख्या 52 ग्रौर 53 को वापस ले लिया जाय ।

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: I withdraw my amendment 17.

SHRI SRINIBAS MISRA: Except amendment 54 I would like to withdraw my other amendments.

SHRI B. P. MANDAL: Sir, I withdraw my amendment 132.

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Sir I withdraw my amendment No. 188.

Amendments Nos. 17, 52, 53, 132 & 188 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is:

Page 9, line 10, add at the end-

"and the Lokpal or Lokayukta as the case may be, may, if satisfied that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2)." (54).

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 9, as amended, stand part of the Bill." The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clause 16—(Procedure in respect of investigations).

SHRI B. P. MANDAL: I beg to move:

Page 9,-

after line 27, insert____

"Provided that no legal practitioner shall be allowed to appear on behalf of any party in course of such investigation." (133).

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move:

Page 9,---

omit lines 14 to 18 (150).

Page 9, line 20,-

for "offer his comments on such complaint or statement" substitute "explain his action." (151).

Page 9, line 27,-

for "during or after the investigation" substitute "or during the investigation." (152).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 10, line 9,-

omit "and the public servant concerned." (189).

श्री बि० प्र० मंडल : सभापति जी, मेरा नंगोधन है कि :

"Provided that no legal practitioner shall be allowed to appear on behalf of any party in course of such investigation."

र्मं चाहता हूं कि लीगल प्रैक्टीणनर न रहे क्योंकि उसके बारे में गांधी जी ने 'My Experiment with Truth.

में लिखा है ग्रौर मुझे भी कुछ दिन मैंजिस्ट्रेट 1905 (ai) LS-17. रहने का मौका मिला है धौर मैं जानता हूं कि हर दम यह कहना कि लीगल प्रैक्टीशनर की जरूरत है ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि लोकपाल और लोकायुक्त को वकीलों, ऐडवोकेट लोगों के हाथ से प्रलग रखना चाहिए। नहीं तो झंझट होगा और लेंगी प्रोसेस होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि लीगल प्रैक्टीशनर ून रहे।

182

श्वी रामाक्तार झास्त्रो : सभापति जी, मेरे तीन संशोधन हैं । पहला संशोधन यह है कि पंक्ति 14 से 18 तक को हटा दिया जाय क्योंकि उसकी कोई ग्रावश्यकता नहीं है । उसमें यह बात कही गयी है कि कोई कम्पलेन्ट करे तो उसकी कोपी या ग्रगर खुद लोकपाल या लोकायुक्त कोई इंवेस्टीगेशन करे नो उसकी ग्राउन्ड वह सम्बन्धित कर्मचारी को ग्रीर कम्पीटेंट ग्रथौरिटी को भेजे । इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

क्लाज (वी) में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"offer his comments on such complaint or statement."

मेरा कहना है कि इस को हटा, कर वहां कहा जाय कि सिर्फ झाप अपने ऐक्शन को एक्सप्लेन कीजिये । उन को यह मौका क्यों दिया जाय कि ग्राप एक्सप्लेन कीजिये । जब चार्ज है तो लोकपाल का कर्त्तंब्य होना चाहिए कि उन से कहे कि ग्राप के ऊपर यह चार्ज है इस के बारे में ग्राप को क्या, सफ़ाई देनी है वह दीजिये ।

आखिरी संशोधन यह है कि :

"during or after the investigation." ग्रगर कोई इनक्वायरी हो रही है नो यह बात ठीक है कि इनक्वायरी के समय में जो गवाह है उसका नाम या ग्रगर किसी के ऊपर कोई चार्ज है उसका नाम नहीं बतलाना चाहिए े[श्री राणवतार जास्त्री]

जनताको उस के पहले श्रीर इनक्वायरी के समय में । लेकिन बाद में बतलाने में क्या दिक्कत है मेरी समझ में नहीं द्याता ।

श्रगर किसी ने गलती की है, अप्टाचार किया है उस पर कोई ग्रारोप है तो जब फैसला हो जाय तब बतलाने में क्या ग्रापत्ति है। इसको बतलाना चाहिए ताकि जनता समझ जाय कि फलाने ग्रफसर या फलाने ग्रादमी ने इतना बड़ा अप्टाचार किया ।

उसी तरीके से किस ने ऐसा काम किया त्रोर किस के कहने से किया जो गवाह है उसका नाम भी बतलाया जाना चाहएि ताकि जनता को यह भी मालूम हो कि हमारे जनतन्व में ऐसे जागरूक लोग हैं जो ग्रगर कोई ग्रफ्सर या मिनिस्टर या ग्रोर कोई गलत काम करता है, श्रघ्टाचार के ग्रभियोग में पकड़ा गया है उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। यह ठीक है कि एनक्वायरी के बीच में ग्राप उस का नाम न बतलाये लेकिन बाद में इस तरह के काम करने वालों ग्रोर गड़बड़ करने वालों का नाम जरूर बतलाना चाहिए।

मेरे ये तीन संशोधन हैं श्रीर मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उन को स्वीकार करेंगे ।

श्री ग्रोम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, इस विधेयक के क्लाज 10 में ग्राया है कि :

In any case where the Lokpal or Lokayukta decides not to entertain a complaint or to discontinue any investigation in respect of a complaint he shall record his reasons thereof and communicate the same to the complainant and the public servant concerned.

मेरा इसमें आब्जेक्शन यह हैकि किसी ने शिकायत की किसी गवनं मेन्ट सर्वेट के खिलाफ ग्रीर वह उसको ठीक मानता है कि गड़बड़ हुई है, लेकिन लोकपाल या लोकायुक्त ने उसमें कोई दम नहीं देखा या शिकायत गलत साबित हई तो उसको गवर्नमेंट सर्वेट के पास क्यों भेजा जाय । उस को कम्प्लेनेन्ट के पास भेजा जाय यह ठीक है लेकिन पब्लिक सर्वेंट के पास जिस के खिलाफ जिकायत को गई है भेज देने के अर्थ यह होंगे कि कोई भी आदमी किसी ग्रफसर के सम्बन्ध में शिकायत करने का साहस नहीं करेगा। हो सकता है कि उस ने ईमानदारी के साथ शिकायत की हो लेकिन वह बात लोकपाल ग्रीर लोकायक्त की समझ में न ग्राई हो। ऐसी स्थिति में शिकायत करने वाले के पास उस को भेज देना ठीक है मगर पब्लिक सर्वेंट के पास भेजने की बात को मैं ठीक नहीं समझता । चंकि शिकायत करने के बाद ग्रादमी के सामने कठिनाई आ सकती है क्योंकि जिस ग्रफसर के ग्रन्डर में वह काम करता है उसके खिलाफ शिकायत गलत साबित होने पर उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड सकता है इस लिए भय के कारण कोई ऋफसर की शिकाय∺ नहीं करेगा । इसलिए इस वाक्य को हटा देना चाहिए कि पब्लिक सर्वेट के पास भेज दिया जायग ।

श्री विद्या चरण शक्ल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री मंडल चाहते हैं कि इस में वकीलों को न जाने दिया जाय । इसके बारे में प्रवर समिति में काफी चर्चा हो चकी है। ज्यादातर सदस्यों का यही खयाल था जो श्री मंडल का है कि वकीलों को जाने से बहत सी कठिनाइयां इस सम्बन्ध थें पैदा हो सकती हैं। इसी लिये हम लोगों ने इस क्लाज में नय किया कि जो लोकपाल या लोकायक्त हैं वह स्वयं ग्रपनी रीति ग्रथव। प्रोसीजर को तय करेंगे । उन्हें इस बात का ग्रधिकार रहेगा कि वह चाहें तो वकीलों का ग्राना रोक सकते हैं। ऐसे भी मामल ग्रा सकते हैं जिनमें बहुत गरीब ग्रीर ऐसे लोग जो सरकारी नौकर हैं जो लोकायक्त भीर लोकपाल के सामते जाकर ग्रंपती जिकायर)

को स्वयं नहीं रख सकते ठीक से और उनको किसी सफाई देने वाले की आवश्यकता हो सकती है, ऐसी स्थिति में लोकपाल कौर लोकायुक्त के पास इस बात का अधिकार रहेगा कि अगर किसी एप्रोप्रिएट केस में वह चाहे तो उनको आने दे। पर इसमें यह साफ बात है कि उनको इस बात का अधिकार भी दिया गया है कि जब वह अपने रूल्स और प्रोसीजर बनायेंगे तब चाहें तो वकीलों का आना बन्द कर सकते हैं। उनको इस बात का पूर्ण अधिकार रहेगा। इसलिये श्री मंडल के संशोधन का जो उद्देश्य है वह इस धारा से पूर्ण हो जाता है। मैं उम्मीद करता हू कि इस बात को देखते हुए वह अपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे।

जहां तक श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन का सवाल है, मैं बतलाना चाहता ह कि लोकपाल ग्रौर लोकायुक्त की जो कार्रवाई होती है वह म्रन्तिम कार्रवाई नहीं है । प्राइमा फेसी केस हैं या नहीं इसको जानने की बात है। उनका जो ग्रमेंडमेंट है उसमें उन्होंने कंहा है कि लाइन 14 से 20 तक हंटा दिया जाये। इसका मतलब होगा कि अगर हम किसी भी सरकारी किर्मचारी से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो जो कापी आफ दि कम्प्लेन्ट है वह नहीं मिलेगी। हमारी जो रीति है, जैसा बिल में रखा गया है, उसके अन्तर्गत पहले कापी देनी होगी जो स्नारोप लगाये गये हैं उनकी ग्रौर उसके बाद वह जवाव देगा। यदि पहले हम एक्सप्लेनेशन मांगें ग्रौर कापी बाद में मिले तो एक्सप्लेनेशन किस बात का मिलेगा ? अगर इस संगोधन को मंजुर कर लिया जायेगा तो जो प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया है उस में बाधा पडेगी 1

तीसरा मंगोधन है कि जो झादमी शिकायत करे उसका नाम भी मामने झाना चाहिये झौर जिसके खिलाफ शिकायत करे उसका नाम भी आना चाहिये जैसा मैं कह रहा था जब केस के ऊपर निर्णय झा जाय तब उस व्यक्ति का नाम झा जाय तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब तक निर्णय न हो और निर्णय के बिना ही उसका नाम फैला दिया जाय और कहा जाय कि इस के खिलाफ अप्टाचार की शिकायतें हैं, यह काररंवाई हो रही है,वह कारवाई हो रही है, उसकी बहुत बदनामी हो जाय ग्रौर बाद में वह निर्दोष सिढ हो जाय तो बदनामी के कारण उसको कष्ट सहना पड़ेगा वह तो हो ही जायेगा ।

श्री रामावतार शास्त्रीः 'ड्यूरिंग ग्रारं स्राफ़-टर दि इन्वेस्टिगेजना'

श्री विद्या चरण शक्त : मैं बतला रहा ह । ग्रापटर इन्वेस्टिगेशन भी चार्ज सिद्ध नहीं हम्रा तो लोकपाल ग्रौर लोकायुक्त जो काम करेगे, जो उनकी फाइंडिंग होगी उसके डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के लिये बाद केस जायेगा क्योंकि सजादेने का अधिकार लोकपाल ग्रौर लोकायक्त को तो नहीं है। वह तो केवल प्राइमा फेसी केन है या नहीं यह देखते हैं । वह ऐप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल ऐक्शन के लिये भेजेंगे । डिपार्टमेंटल ऐक्शन की कार्रवाई पूरी हो जायेगी, उस के बाद सजा मिलेगी । लोकपाल ग्रौर लोकायक्त की कार्रवाई के बाद अपराध सिद्ध नहीं हुआ, पर अपराध किया ह इसकी संभावना व्यक्त होती है इसलिये वहां भेजते हैं । वह यह कह सकते हैं कि इसका कोई ग्रपराध सिद नहीं हम्रा है इसलिये इस पर कोई कार्रवाई न की जाये । पर कई केसेज ऐसे हो सकते हैं जिन पर कह सकते हैं कि इस पर ग्रपराध करने का प्राइमा फेसी ं के है इस लिये इसे डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के लिये दिया जाये । जिस डिपार्टमेंट से सम्बन्धित होगा वहां जाकर जो डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी का प्रोसेस है वह फालो होगा । वहां पर उसका अपराध सिद्ध होगा या असिद्ध होगा । इस लिये पहले से नाम बतला देना ठीक नहीं होगा । यद्य**ि** कई एसे मामले हो सकते हैं जिन के बारे में ग्राम जनता की काफी रुचि है, काफी कौतूहल है। ऐसे मामलों को छिपा कर रखना

(श्रो विद्याचरण शुक्ल)

किसी भी स्टेज पर उचित नहीं होगा। इस लिये हम लोगों ने इस बिल में यह प्रावधान किया है कि ऐसे केसेज पब्लिक हिम्ररिंग के लिये हो सकते हैं। वह इन कैमेरा हिम्ररिंग के लिये जायें यह ग्रावश्यक नहीं है । इस तरह के निदेश लोकायुक्त ग्रीर लोकपाल को दिये गये हैं कि जो मामले या मुकदमे ऐसे हैं जिनमें वह ममझते हैं कि आम जनता को काफी रुचि या कौतुहल है, जिनकी इम्पार्टेसें इतनी है, उन्हें ग्रामजनता कि सामने खोल कर रखना चाहिये शरू से । लोकपाल को ग्रधिकार है कि वह ऐसा कर सकते हैं। इस लिये मैं नहीं समझता कि हमें ऐसा प्रावधान करना चाहिये कि हम सब केसेज खोल दें जिनमें आधे लोग बेचारे अन्त में निर्दोष सिद्ध हों । इसलिये पहले से नाम ग्रा जाय इससे न्याय परा होने की स्थिति नहीं होगी 🚺

में माननीय सदस्यों से निवदन करूंगा कि उन्होंने जो संशोधन मूव किये हैं उन्हें वह इटा लें ग्रेंद इस क्लाज ो जैये का तैसा पास कर दें।

श्री ग्रोम प्रकाश त्यागी : मेरी बात का जवाब नहीं दिया गया । गवर्नमेंट सर्वेट्स के पास कम्प्लेंट के भेजने का क्या तात्पर्य है ? किसी की शिकायत को लोकपाल ने ठीक नहीं समझा तो उसको कम्प्लनेंट के पास भेज देंगे साथ ही जिसकी शिकायत है उसके पास भेज देंगे, इस का क्या मतलब है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इसकी प्रकिया जो है उसको लोकपाल श्रौर लोकायुक्त स्वयं तय करेंगे कि उसमें क्या करना है ।

श्री ग्रोम प्रकाश त्यागी : फिर गवर्न मेंट सर्वेट के पास भेजने का क्या मतलब है ? तब कोई शिकायत ही नहीं करेगा ।

श्वी विद्या चरण झुल्लः यदि किसी के खिलाफ शिकायत है श्रीर उसका हम एक्स- भ्लनेशन चाहें तो उसके पास शिकायत का प्रारूप तो भेजना ही पड़ेगा ।

श्री क्रोम प्रकाझ त्यागी : इस तरह से नहीं । ग्रगर लोकपाल उसको ठीक नहीं समझता है तो वह कम्प्लेंट को वैने ही वापस कर्दूरें, जिसके खिलाफ शिकायत है उसके पास क्यों भीजा जायेगा ?

16 hrs.

भी विद्या चरण शुक्ल : ग्रापकी अमेंडमेंट का नम्बर क्या है ?

श्री ग्रोम प्रकाश त्यागी : मेरी एमेंडमेंट है पेज 10, लाइन 9 पर

श्वी विद्यां चरण झुक्ल : जब भी लोकपाल किसी के खिलाफ इनक्वायरी करना चाहता है तो उस कम्प्लेंट की कापी को उस सरकारी प्रधिकारी के पास वह भेजता है थ्रौर उससे कहता है कि वह उसके बारे में जो कहना चाहे कहे । सरकारी प्रधिकारी को यह पता रहता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात हो रही है । उसको पता रहता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला ...

श्री म्रोम प्रकाश त्यागीः ऐसा नहीं है। पेज 10 पर म्रापने कहा है:

"In any case where the Lokpal or a Lokayukta decides not to entertain a complaint or to discontinue any investigation in respect of a complaint, he shall record his reasons therefor and communicate the same to the complainant and the public servant concerned."

श्री विद्या चरण शुक्लः मैं समझ गया हूं। प्राकृतिक न्याय के लिये यह बहुत जरूरी है, इसलिए इस अमेंडमेंट को मैं मंजूर नहीं कर सकताहं।

श्री म्रोम प्रकाश ित्यागीः कोई रीजन भी तो दें। श्री विखा चरण शुक्स : मैं बहुस नहीं करना चाहता हूं । लेकिन जो प्रक्रिया हमने यहां रखी है उसमें एक स्वाभाविक भौर एक प्राकृतिक न्याय देने की बात हमने कही है । इस प्रक्रिया में जरा भी फेरबदल किया जाएगा तो न्याय नहीं मिलेगा ।

भी भोम (प्रकाश (स्वागी): शिकायत करने वाला प्राफिससं के खिलाफ शिकायत करेगा लेकिन लोकपाल ने प्रगर उस शिकायत को ठीक नहीं समझा तो फिर उस मामले को खित्म करो । ग्राप उस कम्पलेंट को प्रफसर के पास क्यों मेजते हैं। कहां तो प्राप यह कह रहे हैं कि बदनामी न हो जाए लेकिन फिर भाप उस शिकायत को प्रफसर के पास मेज देंगे। इससे उसकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। उसके पास भाप क्यों फिर उस शिकायत को भेज रहे हैं। कुछ, लक्ष्य तो मापका होगा इसको रखने में ? कंसर्न्ड पब्लिक सबेंट के पास माप फिर इसको क्यों मेज रहे हैं ?

SHRI B. P. MANDAL: I beg to leave of the House to withdraw my amendment.

Amendment No. 133 was, by leave withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the other amendments to clause 19 to vote.

Amendments Nos. 150, 151, 152, 189 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 10 stand and part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11- (Evidence.)

SHRI SRINIBAS MISRA: I beg to move:

Page 11, line 9,—after "shall" insert—'unless the investigating authority after examining the question specifically so directs," (55).

Page 11, line 25, for 'binding and conclusive' substitute 'prima facie evidence of such nature'. (56)

Page 11, omit lines 26 to 29. (57). SHRI OM PRAKASH TYAGI: I beg to move:

Page 11, line9, for 'person' substitute 'Government employee'. (190),

SHRI SRINIBAS MISKA: Clause 11 speakes about the evidence to be taken by the Lokpal or Lokayukta. It rather aims very high that he will take evidence, untrammelled by all rules, and no person should claim any privilege to secrecy. But I do not understand how after sub-clause (4), the following sub-clause has been put, in, namely—

"No person shall be required or authorised by virtue of this Act to furnish any such information or answer any such question or produce so much of any document—

(a) as might prejudice the security or defence or"

--so far , that is understandable and intelligible but, what about the subclause (b) which follows, namely--

"(b) as might involve the disclosure of proceedings of the Cabinet of the Union Government or any Committee of that Cabinet or of the Cabinet of the Government of any Union territory or of the Executive Council constituted under the Delhi Administration Act, 1966, or of any Committee of such Cabinet or Executive Council....".

Somebody who is asked to give evidence can take shelter under this provision. If a Secretary certifies that this will come under either 5(a) or 5(b), that will be conclusive. I suggest that after 'shall', we should add 'unless the investigating authority after examining the quetion specially so direct'. All these matters should be

491 Lokpal and

[Shri Srinibas Misra]

placed before the Lokayukta or Lokpal; he should look into it and then decide. If he specially directs, it must be produced. If not, it will not be produced.

As regards the last one, that it should be binding and conclusive, it cannot be so. It can be rebutted. Once a certificate is given by a Secretary, it will only mean that on *prima facie* evidence it will come under 5(a) or 5(b). But it is open to the other side to challege that it does not come under either of these.

श्री कोस प्रकाश त्यागी: सब क्लाज 5 में लिखा है "नो परसन शैल वी रिक्वायर्ड"। यानी किस भी आदमी से इस प्रकार का डाकुमेंट नहीं मांगा जा सकेगा जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो या दूसरे देशों के साथ, ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध जो हैं, उनको प्रभावित करता हो ।

किसी भी गवनें मेंट सर्वेंट से इस प्रकार का रिकार्ड मांगा जाए जो हमारी डिफेंस से सम्बन्ध रखता हो या हमारी कैबिनेट की जो प्रोसीडेंग्ज हैं, उनको मांगा जाए तो मैं इस को ग्रनचित समझता हं। इसको नहीं मांगा जाना चाहिए। अगर मांग जाता है तो अगर कोई भी व्यक्तिन दे तो ठीक है। लेकिन मान लो यहां कोई सी ग्राई ए का एजंट है, ग्रमरीका का. रशिया का. चीन का या पाकिस्तान का एजेंट है भ्रौर वह पकडा जाता है श्रौर उसके पास कुछ इस प्रकार के सीकेंट्स हैं जिन के म्राउट होने से पाकिस्तान, रमिया या ग्रमारीका के सम्बन्धों में गडबड होगी तो क्य भ्राप उस एजेंट से डाकूमेंट मांग सकेंगे या नहीं मांग सकेंगे, यह मैं आप से जानना चाइता हं। मैं उदाहरण देता हं। मान लो किसी जगह पर कम्युनल रायट हो जाता है ग्रीर मान लो कि उस कम्यनल रायट में किसी विश्वेष बर्ग, मान लो मसलमा रों के साथ कोई बडा अत्याचार हो जाता है भौर वह किसी एजेंट के कारण होता है

और हो सकता है कि वह ब्रादमी यह कह दे कि इस डाकूमेंट के प्रकट होने से इसका प्रभाव हिन्दुस्तान मौर पाकिस्तान के सम्बन्धों पर जा कर पडेगा. तो क्या इस कारण से उस डाकूमेंट को ग्राउट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मान लो चीन का कोई गैंप्रेंट पकड लिया जाए झौर वह कहता है कि जो डाकुमेंट है उसको मैंने दे दिया तो जो तुम्हारे सम्बन्ध बने हुए हैं वे बिगड जायेंगे या ग्रमरीका का भादमी पकडा जाता है सौर वह कहता है कि तुम्हारे सम्बन्ध ममरीका के साथ खराब हो जाएंगे, तो क्या इस कारण से झाप उस डाकसेंट को माउट करने की माप इजाजत नहीं देंगे ? मगर सरकार न देतो बात समझ में झाती है लेकिन ग्रापने तो लिखा है "नो परसन" इस में तो एजेंट भी ग्रा जाएगा। ग्रब वह एजेंट आपको वह कागज देगा या नहीं ? इस वास्ते मैंने सुझाव दिया है कि नो परसन की जगह गवर्नमेंट एम्प्लायी कर दें। ग्रगर कोई एर्जेंट पकडा गया और उसने यह प्ली लेली तो ग्राप कुछ नहीं कर सकेंगे। यहां पर इस प्रकार के वकील हैं, एडवोकेट हैं, जो चोरों का, डाक्रुफ़ोंा ग्रांर गटारों का भी साथ देते हैं। स्नाप उस अवस्था में इस का क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। इस वास्ते नो परसन की जगह ग्राप गवर्नमेंट एम्प्लायी लिख दें।

भी विद्या करण शुक्स : सिश्व जी ने प्रपने संशोधन में कहां है कि क्लाज 11 (5) (ए) का संशोधन किया जाए गौर एक एक्सैपशन किया जाए ताकि जो सर्टिफिकेट कोई सैकेटरी या गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, उसको वह ग्रोवर राइड कर सके ग्रीर जो डाकुमेंट हम नहीं देना चाहते हैं उनको देने के लिए भी वाध्य किया जा सके। सवाल इतना ही पैदा है कि यदि कैविनेट को फंकशन करना है तो कैबिनेट के डाकुमैंट या कैबिनेट प्रोसीडिंग्ज यदि इनको भी हमें देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो फिर

कैंबिनेट सिस्टम जो है, उसको चलाये रखना बिल्कूल मश्किल हो जाएगा, कैंबिनेट का जो हमारा काम चल रहा है. उसका चलना बिल्कुलं मश्किल हो जाएगा । इसके उपर हमने काफी सोच विचार किया है। दूसरी बात यह है कि एम्बुट्जमैन के जो विधेयक बाहर बने हैं इसके सम्बन्ध में कानन बाहर बने हैं, उनकी तरफ भी हमने ध्यान दिया है। हमने देखा है कि जहां यह संस्था ग्रच्छी तरह से कान कर रही हैं. ्उनके वहां भी यह प्रा<mark>वधान</mark> है कि <mark>यदि सरकार</mark> दारा कोई कागज या सूचना प्रकट किये जाने पर जन-हित की हानि की आशंका हो, तो सरकार के लिये उस कागज या सचना को भेजना आवश्यक नहीं है और जब इस त्राशय का सटिफिकेट सेकेटरी द्वारा दिया जाये, तो उसको मजर कर लिया जाये । इसलिये मैं र्रेनहीं समझता कि हम माननीय सदस्य के संशोधन को मंजर कर सकते हैं। त्रगर ऐसे डाकूमेंट पेश कर दिये जायें, तो जो बाद में सबके सामने आ जायें. तो उनसे दूसरे देशों के साथ हमारे मैबीपूर्ण सम्बन्ध नष्ट हो सकते हैं सौर ग्रागे चल कर बढी कठिनाई पैदा हो सकती है।

श्री त्यागी ने यह संशोधन रखा है कि "पर्सन" की जगह "गवर्नमेंट इम्प्लाई" रख दिया जाये। हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था को जरूर वाइड रखा जाये, ताकि इसके अन्तर्गत न केवल सरकारी कर्मचारी, बल्कि हर एक व्यक्ति ग्रा सके। इसको रखने से लोकपाल ग्रौर लोकायुक्त को यह ग्रधिकार होगा कि वे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या न हो, बुला सकें श्रीर इस बारे में कार्यवाही कर सकें। "गवर्नमेंट एम्प्लाई" शब्द रखने से पब्लिक सेक्टर के एम्प्लाईज, युनिवन टेरीटरीज में म्युनिसिपल कारपोरेशन या म्यूनिसिपल कसेटी के कर्मचारी इसके अन्तर्गत शामिल नहीं होंगे, वे इस प्राविजन के परिधि से बिल्कुल बाहर हो जायेंगे । इसलिये ''गवर्नमेंट एम्प्लाई'

के बजाये "पर्सन" रखना ही उचित होगा ।

श्री ग्रोम प्रकाश त्यागी : मान लीजिये कि किसी कन्ट्री का कोई एजेन्ट पकड़ा जाता है ग्रीर वह इस व्यवस्था का लाभ उठा कर कहता है कि ग्रगर वह ग्रमुक कागज या सूचना पेश करेगा, तो उस कन्ट्री के साथ उदाहरण के लिये रशा के साथ, रिलेशन्ज खराब हो जायेंगे । मंत्री महोदय का इस बारे में क्या कहना है ?

श्वी विद्यावरण सुक्त : उसके ऐसा कहने से कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि सरकारी प्रधिकारी स्वयं इस प्राशय का सटिफिकेट न दे । किसी व्यक्ति के सटिफिकेट देने या कहने से काम नहीं चलेगा । लोकपाल या लोकायुक्त के पास मंति-मंडल के सचिव या सरकार के किसी ग्रन्थ सचिव की तरफ से जो सटिफिकेट दिया जायेगा, केवल वही लागू होगा, किसी में व्यक्ति का सटिफिकेट लागू नहीं होगा । यदि कोई व्यक्ति कहता है फि अमुक कागज या सूचना को प्रकट करने से हमारे मिन्न देशों के साथ सम्बन्धों में नुकसान होगा, तो वह सटिफिकेट लोकपाल या लोका-युक्त पर लागू नहीं होगा । इसलिये माननीय सदस्य ग्रयने संशोधन को प्रेस न करें ।

MR. CHAIRMAN: Have Mr. Tyagi and Mr. Misra leave of the House to withdraw their amendments?

Amendments Nos. 55 to 57 and 190. were by leave withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is: "That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

- Clause 11 was added to the Bill.
 - Clause 12—(Reports of Lakpal and Lokayuktas.)
 - SHRI LOBO PRABHU: I move: Page 12, line 22.---

for "President" substitute "Speaker" (77). [Shri Lobo Prabhu]

Page 12, line 30,-

for "President" substitute "Speaker" (78).

SHRI OM PRAKASH TYAGI: I move-

Page 12, line 27,---

add at the end—

"and the President shall cause it to be laid before the Parliament within three months." (192).

SHRI LOBO PRABHU: Sir, in these amendments and some others which have already been passed over, I have raised a fundamental issue whether the Lokpal will be a Commissioner for the Parliament or a Commissioner for the Government. There is a vital distinction of the Lokpal being under the President and being under the Speaker. If the Lokpai is under the President, according to the present constitutional practice, he is under the orders of the Government, the Prime Minister and of her Ministers concerned. He is by no means independent. The question is: when he differs from the Government, when he differs from the Prime Minister. functions through and he the President, has he a fair chance of presenting his case? Is the President likely to differ from the Prime Minister or the Minister concerned? The President has been unfortunately a rubber-stamp according to our constitutional practice. He is bound to take the advice of the Prime Minister. How can he then, when he gets these papers showing difference of opinion, between Lokpal and the Prime Minister, have his own difference of opinion? It means this: that if you interpose the President, any power to differ from the Government for the Lokpal, would be a redundant exercise serving no purpose. It is almost deceiving the people.

Not only is this a constitutional impasse. There is the fact that the President and the Government have not been able to take sufficient work,

sufficient use, from the authorities they have previously appointed to control corruption. I refer to the Grievance Commissioner and to the Vigilance Commissioner. I need not tell this House that this Grievance Commissioner, after existing for about three years, was ultimately found to be useless and was abolished, As far as the Vigilance Commisioner is concerned, the last report of the Home Ministry showed that while he began with a list of 6,000 complaints in the first year, last year those complaints were reduced to only 1,000. The people had so quickly lost their faith in this Vigilance Commissioner as they had lost faith in the Grievance The only reason for Commissioner this is that he was part of the Government: he was a limb of the very persons whom he was supposed to We have a theory here that check. the Government can do no wrong: the divine right that the King can do That theory extends to no wrong. every Government servant!

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI LOBO PRABHU: I am concluding. This is a very vital issue.

MR. CHAIRMAN: Please speak on your amendment only.

SHRI LOBO PRABHU: This is my amendment. My amendment, therefore, is that for the word "President" wherever it occurs and particularly in this section substitute the word "Speaker." The Speaker is the representative of the House. The Speaker is the competent authority to appoint many officials; he has his Secretary and all the other staff. I cannot see why the Lokpal should not be under the Speaker.

I would like the Minister to carefully consider this. You must give confidence to the people. You must not give them the feeling that their complaints are just being addressed to a blank wall and that they are only indulging in an exercise of futility. If you make this change, while it may appear to be a big change, you will be giving the Bill some form of eredibility a_S far as the public is concerned.

श्री झोम प्रकाश त्यागी: समापति महोदय, सब-क्लोज (6) में कहा गया है कि लोकपाल भौर लोकायुक्त प्रपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हाँ कि हमारे संविधान के प्रनुसार लोक सभा को सर्वोच्च सत्ता मान गया है। इस लिए देश भर के प्रत्येक सरकारी कार्य का विवरण लोक समा के सामने ग्राना ही चाहिए, चाहे वह किसी के छू आये, प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट या स्पीकर के प्रु प्राये, जिससे देश की स्थिति का पूरा चित्र लोक सभा के सामने मा सके । मौर एक व्यवस्था कि लोकपाल किस ढंग से कार्य कर रहे हैं वह उस के सामने ग्रा सके। इसलिए जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट ग्राए तो मेरा ग्रमेंडमेंट यह है कि

"and the President shall cause it to be laid before Parliament within three months".

तीन महीने के अन्दर प्रेसीडेंट साहब को जो वार्षिक रिपोर्ट मिली है वह, पालिया मेंट के सामने उपस्थित कर देनी चाहिये । यह मेरा सुझाव है । अगर प्राप इत को नहीं रखते हैं त्रोर वह रिपोर्ट केवल प्रेसीडेंट तक ही , रह जाती है तो मैं समझता हूं कि संविधान , की भावना पर मी पालिया मेंट की लोक सत्ता पर भी आघात आता है । इसलिए यह शब्द जोड़ दिए जायं, यह मेरी प्रार्थना है ।

श्री विद्याचरएग शुक्ल : प्राध्यक्ष महोदय, श्रीमान लोबोप्रभू ने यह कहा है कि जो लोकपाल की रिपोर्ट ग्राए उसे स्पीकर के पास भेजना चाहिए, प्रेसीडेंट के पास नहीं । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोकपाल की रिपोर्ट ग्राएगी उसे गवर्नमैंट के एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पेश करना पड़ेगा ग्रीर गवर्ननैमेंट के ऊपर इस कानून के ग्रन्तगंत एक बन्घन लग गया है कि उन्हें वार्षिक रूप से इस रिपोर्ट को सदन के सामने रखना ग्रावश्यक है । इस

लिए रिपोर्ट स्पीकर के पास थदि ग्राए ग्रौर स्पीकर हाउस के सामने रख दे. उस में गवर्न-मैंट का एक्सप्लेनेशन न रहे तो माननीय सदन को यह बात ठीक समझ में नहीं ग्राएगी कि यदि उस रिपोर्ट में कोई ऐसी बातें हैं जिन को गवर्नमेंट ने मंजुर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो उस का एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम जो गवर्नमेंट को देना है वह तब तक नहीं ग्रा सकता जब तक कि प्रेसीडेंट उस रिपोर्टको न ले ग्रौर गवर्नमेंटका एक्स-प्लेनेटी मेमोरेंडम ले कर उस को सदन के सामने न रखे। वह चीज सदन के सामने ग्राएगी क्योंकि इस का प्रावघान इस विघेयक में किया गया है। दूसरी बात यह है कि जैसे कम्प्टोलर ऐंड ग्राडीटर जनरल की रिपोर्ट है वह भी प्रेसीडेंट को जाती है, वह भी स्पीकर के पास नहीं आती, प्रेसीडेंट के पास माती है और गवर्नमेंट उस में जो ब्यौरा देती है जो मपना एक्सप्लेनेशन देती है उस के साथ वह सदन के सामने आती है। इसलिए जो प्रक्रिया बनी है कि जब इस माननीय सदन के सामने वह रिपोर्ट ग्राए तो उसमें गवर्न-मेंट का भी पूरा ब्यौरा एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ रहना चाहिये वही प्रक्रिया ज्यादा ग्रच्छी होगी कि बजाय स्पीकर के प्रेसीडेंट के पान वह रिपोर्ट ग्राए ग्रौर वहां से हर साल जैसे ग्रौर रिपोर्ट्स को यहां रखना पड़ता है वैसे ही गवर्नमेंट के मेमोरेंडम के साथ यह रिपोर्ट भी यहां म्राए। इसलिए जो प्रक्रिया 🛛 रखी गई है वहीं रखनी चाहिए ग्रौर स्पीकर के पास रखने में उस में देर होगी। स्पीकर को फिर सरकार के पास भेजना पडेगा ग्रौर सरकार फिर देखभाल करेगी ग्रौर तब ग्रपनी रिपोर्ट उस पर यहां पेश करेगी. तब मान-नीय सदस्य उस पर सोच विचार कर सकेंगे। शरू से दोनों चीजें एक साथ आ जायेंगी तो उस रिपोर्ट पर विचार करने में सुविधा होगी ।

उसी तरह से माननीय त्यागी जी ने जो व्रपना प्रमेंडमेंट दिया है उसमें वह चाहते हैं कि तीन महीने के ग्रन्दर इस रिपोर्ट को [श्री ग्रोम प्रकाश त्यागी] 🕛

सदन के सामने पेश किया जाय। मैं उन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हं कि पैरा 7 के ग्रन्तर्गत वार्षिक रूप से इस सदन के सामने इस रिपोर्ट को सरकार को पेश करना पडेगा । उसमें किसी तरह का बीच बचाव नहीं है कि सरकार देर कर सके। ग्रगर देर होने की संभावना होती तो मैं ग्राप का ग्रमेंड-मैंट जरूर स्वीकार कर लेता । लेकिन क्यों कि हमने खद इस का प्रावधान किया है कि वार्षिक रूप से यह रिपोर्ट सदन के सामने ग्राए जैसे य० पी० एस० सी० की या म्राडीटर जनरल की ग्राती है ऐसे ही यह भी ग्राए इसलिए उसे स्वीकार करने की ग्रावश्यकता नहीं है। यह कहना कि तीन महीने के ब्रन्दर रिपोर्ट ग्रानी चाहिए, उस से कोई लाभ नहीं है क्योंकि इस में प्रावधान है कि जैसे वांषिक बजट स्राता है या यू० पी० एस० सी० की रिपोर्ट ग्राती है, ग्राडीटर जनरल की रिपार्ट आत, है ऐसे ही इस को भी सदन के सामने रखा जाय। उस को जोडने से कोई विशेष फायदा नहीं है। इस लिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधनों को वापस ले लें।

MR. CHAIRMAN: Shall I put all the amendments to the vote of the House?

SHRI LOBO PRABHU: Sir, I may be permitted to press my amendments, because they are very important and I believe in them.

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment Nos. 77 and 78 to the vote of the House.

Amendments Nos. 77 and 78 were put and negatived.

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Sir, 1 want to withdraw my amendment.

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member the leave of the House to .withdraw his amendment?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

Amendment No. 192 was, by leave, withdrawn

MR. CHAIRMAN: I will now put clause 12 to the vote of the House.

शो म्रोंकारलाल बेरवा (कोटा)ः वैयरमंत

महोदय, यह कैसे पास कर पहे हैं, सदन में कोदम नहीं है।

MR. CHAIRMAN: The bell is being rung ... Now there is quorum. The question is:

"That clause 12 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clauses 13 to 15 were added to the Bill.

Clause 16-(Protection.)

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I move:

Page 14, lines 28 and 29,---

for "or any member of their staff and employees"

substitute—

"or against any officer, employce, agency or person referred to in section 13" (11)

This amendment has been found necessary to give protection to the agencies or persons referred to in clause 13 in respect of anything which is done in good faith. It is slight amendment which is being moved so that they are protected for any action taken by them in good faith.

MR. CHAIRMAN: The question is: Page 14, lines 28 and 29,---

> for "or any member of their staff and employees"

substitute---

"or against any officer, employee, agency or person referred to in section 13" (11)

The motion was adopted.

. . .

... MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clause 17 was added to the Bill

Clause 18- (Power to exclude complaints against certain classes of Public Servants.)

SHRI SRINIBAS MISRA: I do not want to move my amendment. I will only commend to the Government to be consistent and logical. Here, it says, "a minimum monthly salary (exclusive of allowances) of one thousand rupees or more". What is the minimum? One thousand rupees or more? You say, it will be one thousand rupees or more. It is illogical. If you say, a minimum of one thousand rupees, it is all right. Why say a minimum of one thousand rupees or more? To make it logical, I suggest, it should be a monthly salary of one thousand rupees or more. To add the word "minimum" or will not add to the dignity of the drafting or will not give them any more facility or make it more comprehensive.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Actually, it is kept at the discretion of the Lokpal. It is done on his recommendation. This is necessary to ensure proper and efficient functioning of the institution. Otherwise, so many cases may come to the Lokpal and Lokayuktas and their proper functioning will become impossible. So, I would request the hon Member, in view of the practical difficulties that we have, not to press that.

SHRI SRINIBAS MISRA: You say, a minimum monthly salary of one thousand rupees or more. Is minimum one thousand rupees or more? Minimum must be a fixed sum. You say, minimum of one thousand rupees or more, that is, two thousand rupees may be minimum or even five thousand rupees may be minimum. Why do you say "minimum"? Why don't you say one thousand rupees or more?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Almost all the posts in Government do not carry a fixed salary. They have a scale of pay having a minimum and a maximum for a span of years. Therefore, it will be necessary to specify the posts which carry a minimum; more cannot be added or excluded by the notification. The allowances attached to the post may vary. So, to have a uniform treatment, it will be necessary to go by the salary attached to the post without allowances at arriving the figure of one thousand rupees.

SRI SRINIBAS MISRA: He is defending something indefensible. You say a minimum of one thousand rupees or more. You may say, a minimum of one thousand rupees. What is the meaning of "more"? Does it carry any meaning?

श्री ग्रटलविहारी वाजपेयी (बलरामपुर): समापति जी, ज्ञायद मतलब यह है कि तन-ख्वाह कम से कम एक हजार होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है, मैं माषा के बारे में कुछ नहीं कह सकता; लेकिन मन्ज्ञा ठीक है ।

SHRI C. K. BHATTACHARYYA: (Raiganj): The sentence involves self-contradiction. Either the word "minimum" should be removed or the word "more" should be removed.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We consulted our legal draftsman. There is no contradiction in it. I would say, it should be accepted as it is. We were ourselves concerned when this amendment was received by us. We got it examined.

MR. CHAIRMAN: Now, I put clause 18 to the vote of the House. The question is:

> "Clause 18 stand part of the Bill." The motion was adopted.

Clause 18 was added to the Bill.

[Mr. Chairman]

Clauses 19 to 22 were added to the Bill.

The First Schedule was added to the Bill.

The Second Schedule was added to the Bill.

The Third Schedule

SHRI SRINIBAS MISRA: I beg to move:

Page 18, line 28,-

Page 19,---

omit lines 5 to 9. (61)

Regarding amendment 60, as I have said, it should be plural; it should be 'Governments' and not 'Government', because we are saying 'States'. So, there cannot be only one Government.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I think, it is a proper and good amendment. We accept this.

SHRI SRINIBAS MISRA: I would like to speak on amendment 61. What are excluded from the purview of the Lokpal and Lokayuktas are given in the Third Schedule. Here (f) reads as follows:--

"Action taken in respect of appointments, removals, pay, discipline, superannuation or other matters relating to conditions of service of public servants but not including action relating to claims for pension, gratuity, provident fund or to any claims which arise on retirement, removal or termination of service."

This is self-defeating. If you are appointing Lokpal and Lokayuktas to look into the grievances and allegations of public servants, the citizens of this country, it is not proper that you should exclude these matters from the purview of the Lokpal and Lokayuktas. Therefore, my amendment is that this portion, namely, (f), lines 5 to 9 on page 19, should be omitted.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: This amendment is not acceptable to us because if the personal matters of government employees are also included in the purview of Lokpal and Lokayuktas, it will make the work of Lokpal and Lokayuktas very cumbersome. Therefore, we have excludbersome. Therefore, we have excluded all the personal matters relating to government servants except those which relate to pension, gratuity and provident fund of ex-government servants. Amendment 61 is not acceptable to us.

SHRI SRINIBAS MISRA: I want my amendment 61 to be put to the vote of the House.

MR. CHAIRMAN: I now put amendment 61, moved by Shri Srinibas Misra, to the vote of the House.

Amendment No. 61 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

Page 18, line 28, for "Government" substitute—

"Governments". (60)

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Third Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

SHRI RANGA (Srikakulam): I think that the House has very good reason to congratulate itself on this Bill not that it is . . .

MR. CHAIRMAN: I want to draw your attention to one thing. This is third reading. It is not like the first reading. It is much shorter, only referring to matters which are referred to in the second reading. It should not be a long speech.

SHRI S. S. KOTHARI: I want to speak on the Third Reading.

SHRI SRINIBAS MISRA: A question was asked by an hon. Member from the DMK to know the meaning of Lokpal and Lokayukta. My mother tongue is something which is born from Sanskrit. T understand Lokpal, but this Lokayukta is very difficult for me to understand. The hon. Member has asked ten times so that the hon. Minister may give the meaning. Now, without understanding the meaning of Lokayukta, we are going to pass the Bill in the third reading.

SHRI RANGA: As I said, the House has very good reason to congratulate itself upon this Bill; not that it is entirely satisfactory, but it is because of the initiative taken by members of this House that the Government began to think on these lines and gave thought to the need for such a legislation. I think that the chief credit should go to that grand old national leader, Mr. Munshi, for having for the first time placed before the public the details of this institution known as Ombudsman in Sweden and familiarise the idea of it and press upon the public mind the need for establishing an institution like this. Next, the late Mr. Mathur, who was one of our senior members here. moved a non-official resolution and extracted the promise from the Government that they would think about

this matter very seriously and take the necessary action. Then, the Administrative Reforms Commission came out with detailed proposals and a draft Bill also and gave a form to these two institutions in the manner in which they are indicated in this Bill as Lokpal and Lokayukta.

I agree with my friend. Shri Srinibas Misra, that it would have been much better for the Government to have chosen titles which would make a greater sense than these Sanskrit words and that would have pleased our friends from Tamilnadu also. Nevertheless, we need not quarrel over these names. I am extremely sorry that the Government has chosen to assert its innate conservatism that generally goes with any Government in its refusal to bring the Prime Minister and Chief Ministers within the mischief or within the ambit of this Bill ..

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: This Bill has nothing to do with State administration. It is only concerned with the Union Government.

SHRI RANGA: The Prime Minister has not been brought within it. They thought so much about the Prime Ministership that they were not willing to bring the Prime Minister within the mischief of this Bill. As I said, it is a very conservative attitude because we discussed this matter in the Congress Working Committee of those days just when Mahatma Gandhi was still alive and soon after he died because by that time Congress Ministries had come. Just like a baby which no sooner it comes into the world starts crying, similarly these Ministers also no sooner they become Ministers they begin to indulge in all sorts of wrong practices. Therefore, we wanted to have some check. Then we discussed it at great length. It is a long history. I need not go into that. In fact mentioned it in one of the Commonwealh Parliamentary Conferences also.

[Shri Ranga]

India has some history about this just like so many other democratic countries. The only difference between India and other countries is while Sweden, New Zealand, England and Australia had taken early action. in order to bring this kind of a solace, this kind of an institution into existence and thus protect the people and assure them of some protection against arbitrary action, discrimination on the part of the Government and also corruption from Ministers, our Government had to wait all these years. Why? Because they had a very high, exalted view of the Ministers. So, Sir, Pandit Jawaharlal Nehru said, we cannot think of congress ministers becoming corrupt; and if, by any chance, one or two were to become corrupt, we cannot simply hand them over to some independent officer. So, he devised the idea that any complaint made against congress ministers-at that time we had congress ministers only and no body else in this country-should be dealt with by the Chief Mnnisters concerned. If there were any complaints against Chief Ministers they should be sent up to the Prime Minister here and if any complaints against the Central Cabinet Ministers were there. they should be dealt with by the Prime Minister, But, later on, what happened? We found one of the Prime Minister's personal secretaries indulged in ways of corruption and the Prime Minister was obliged to shed that Secretary and wash his hands off him. Some of the Prime Minister's own colleagues were charged for corruption but he tried to shield them for as long as possible. He tried to shield the Chief Minister in Punjab as you know, till the very last moment. In the end he was forced to his case to an ex-Supreme senđ Court Judge and we know the results. That Chief Minister had to go. two Chief Ministers of Similarly Orissa had also to go. In that way Pandit Jawaharlal Nehru did not give satisfaction to the country nor did

his action bring any honour to him or to the Parliament and that was the reason why when his successor Shri Lal Bahadur Shastri was Prime Minister and when a suggestion was made by Mr. Santhanam's Committee that the Prime Minister and the Chief Minister should be kept out of the purview of this particular legislation I told him that we were not prepared to accept it because we found that the Prime Minister was capable of shielding ministers of doubtful integrity.

Now we come to the third Prime Minister. The third Prime Minister also wants to be kept out of the purview of this Bill. Let us hope that the third Prime Minister would be able to have a much better record than the earlier Prime Ministers so far as colleagues are concerned. Let us also hope-and it would be hoping against hope-that the Prime Minister herself or himself, would not indulge in such bad practices, undemocratic practices as to be charged by the people as undemocratic and discriminatory and dishonest. It is only hoping against hope and that is why I am extremely unhappy that the congress party here could not see its way to accept the amendments moved from this side that the Prime Minister also should be brought within the purview of this particular legislation.

So far as this legislation goes are not quite sure that even these two institutions would be able to give to the country greater satisfaction than the vigilance commissions because it is a matter of time, how long they take to investigate into the complaints and give redress to the people concerned. The other is the question of the costs involved for the ordinary folk to have to invoke the aid of these institutions and place before them the whole of the case and all the evidence and all the rest of it, to prove the charges. Because, after 509 Lokpal and

SRAVANA 29, 1891 (SAKA)

all, on these two anvils of time and of cost, the whole thing rests. If it costs too much or if the people cannot get justice quickly from these institutions, if these institutions were to indulge in too much of delay then, this entire system would fail to yield good results.

I hope, Sir, this Government would try to take the necessary precautions to ensure that not too much time would be aken and the procedure would not be cumbersome and costly to the public in placing their complaints before this institution.

I once again remind the House of its debt of gratitude to Mr. Munshi and Mr. Mathur and I support this Bill.

भौ शिव चन्द्र झा (मधुवनी) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का मौटे तौर पर समर्थन करता हूं । इस विधेयक की आव-श्यकता होगी, यह बात भी साफ है । आजादी के बाद हिन्दुस्तान में जैसी फिजा पैदा हुई है उसमें फ्रष्टाचार बढा है, घटा नहीं है । आज यदि सरकार को इस बात में खुशी है कि फ्रष्टाचार रोकने के लिए एक विधेयक लाई है तो दूसरी तरफ सरकार दोषी भी हो जाती है क्योंकि यब तक का जो सिलसिला देश में रहा इस हुकूमत की वजह से उससे फ्रष्टाचार बढ़ा है, इस सरकार की नीतियों की वजह से हिन्दुस्तान में फ्राष्टा-चार बढा है ।

सभापति जी, इस विधेयक में मिनि-स्टर तक को नहीं छोड़ा गया है, लेकिन प्रधान मंत्री की इन्होंने चर्चा नहीं की है। उनको नहीं लाना चाहते हैं। मतलब यह है कि ग्राजादी के बाद बड़े से बड़े मिनि-स्टर भी भ्रष्ट हो गये हैं यह सरकार कबूल करती है इस विधेयक के जरिये। तो सर-कार कंडेस्ड ग्रीर गिल्टी है, इस से यह साबित होता है। इसलिए ग्राप ने ऐसा कदम बढ़ाया ग्रीर ग्राप समझते हैं कि यह कारगर कदम होगा। तो फिर प्रधान मंत्री को इस दायरे में क्यों नहीं लाये। चाहेमौजूदा प्रधान मंत्री हों, या ग्राने वाले प्रधान मंत्री हों, उन सब को इस विधेयक में लाना चाहिये। यह सोचना कि प्रधान मंत्री दूध के धोये हैं यह धारणा बिल्कुल गलत है। ग्रौर बराबरी की धारणा के भी खिलाफ है।

लेकिन सवाल ग्राता है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ा क्यों ? ग्राजादी के पहले भी वही लोग थे जो ग्राज ग्राजादी के बाद भ्रष्ट हो गये हैं, उन के खिलाफ शिकायतें हैं, चाहे प्रताप सिंह कैरों हों या श्री के० वी० सहाय हों, ग्राजादों के पहले उतनी खराबियां उ: में नहीं थीं । लेकिन क्या वजह है कि ग्राजादी के बाद यह खराब हो गये हैं, भौर इन में खानियां क्यों ग्राने लगीं ? इसकी वृति-यादी वजह यह है कि ग्राजादी के बाद इस सरकार ने देश के सामने एक प्रेरणा रखने का काम छोड दिया है ।

ग्राजादी के पहले सब कूरबानी देने के लिये जाते थे, उन को राज सत्ता से कुछ लेना नहीं होता था। बल्कि बलिदान की भावना रहनी थी। लेकिन ग्राजादी के बाद इन के सामने कोई ग्रादर्श नहीं रहे, मकसद नहीं रहा, और वह प्रेरणा खत्म हो गयी। सोचा कि गही पर क्या गये जितना पैसा कमाना चाहो कमा लो । जो सिलसिला इन्होंने भ्राजादी के बाद चलाया वह सिल-सिला पंजीवादी सिलसिला रहा जिस में ये खामियां ग्रानी हैं । खराबियां बढी हैं नागरिकों के बीच में ही नहीं बल्कि राज्यों के बीच में भी, ग्रौर पंजीवादी व्यवस्था में ऐसा होता ही है। इसलिये भ्रष्टाचार बढ़ गया है । हिन्दुस्तान ही नहीं, स्वीडन् नहीं, जहां ग्रोम्बड्समैन की शरूआत हई दल्कि ग्रमरीका में भी ग्राप को भ्रष्टाचार की बात मिलेंगी। लेकिन एक फर्क ग्राता है ग्रीर वह यह कि उन मुल्कों में जहां शिक्षा बढी हई है और नैतिकता का स्तर कुछ ऊंचा है वहां छोटे भ्रष्टाचार नहीं होते । यहां 5, 10 रू० घुस लेने की बात होती है.

[श्री शिवचन्द्र झा]

ये सब बातें उन देशों में नहीं पायेंगे छोटा भ्रष्टाचार वहां नहीं होता है। वहां भ्रष्टा-चार होज़ा है लाखों की जब बात मानी है तब। तो पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से यह खराबियां हैं। जिस तरह से मौर मुल्कों में भ्रष्टाचार बढ़ा उसी तरह से यहां भी बढ़ा है। जिस में इजाफा किया है सरकार ने भ्रपनी योजनाओं से।

सवाल भाता है कि इस का हल क्या है? हल यह है कि गैर वराबरी को खत्म किया जाय । भ्रौर जब तक गैर वराबरी के सिस्टम को खत्म नहीं करते तव तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। भ्रौर बानों के खलावा एक बात निहायत जरूरी है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये भ्रौर वह यह है कि भ्रामदनी की सीलिंग सरकार रखे ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया। लेकिन जब तक ग्रामदनी पर हदबन्दी नहीं करते हैं एक ग्रीर दस के अनुपात में ग्रीर यह ग्रायिक विषमता रहनी है नो इस के ननीजे ग्रीर भी खराब होते हैं ग्रीर भ्रष्टा-चार ग्राये बढता है।

इसलिये सरकार यदि ईमानदारी से चाहनी है कि देश में भ्रष्टाचार का खात्मा हो, छोटे से कर्मचारी से लेकर मिनिस्टर तक कोई भ्रष्टाचारी न रहे, नो जिस तरह से बैंकों का राप्ट्रीयकरण किया है दृढ़ता के साथ उस ग्रोर कदम उठावे ताकि पूंजीवाद का खात्मा हो ग्रौर समाजवादी व्यवस्था की शुरूआत हो । ग्रौर जब तक ऐसी फिजा पदा नहीं होती है तय तक कुछ होने वाला नहीं है । भ्रष्टाचार को रोकने की फिजा पैदा करने के लिये जो सरकार यह विधेयक लःयी है उस दृष्टिकोण में मैं इस विधेयक का स्वागन करता हूं ।

SHRI NARENDRA SINGH MAHI-DA (Anand): Eternal vigilance is the price of liberty and democracy and I take it that this Bill cautions and warns of corruption in high places. I must confess that standards in public life have gone down after Independence. Restraint should play a part in higher levels of society, especially the State Ministers and Central Ministers. The moment they attain a high position, instead of bringing about self restraint and discipline, they indulge in pemp and show. In order to save democracy and preserve the standards of public life this Bill has It is welcome. become necessary. But by itself, it will solve no problems. As a public servant of 38 years standing, I say that there are some standardas to be maintained; one's behaviour whether in power or out of power should be the same; simplicity should be the watch word. The differences in incomes, say of a person earning Rs. 30 lakhs a year and another earning Rs. 350 a year, create difficulties. The moment a person becomes a Minister, there are many temptations. If we lead a simple life, resist those temptations we can and not be corrupted. But when a person want more and more of comforts he yields to temptations and corruption. One of the causes of corruption is election. Our elections are becoming costlier every day and persons at high places are tempted to receive offers from business houses and others to meet the election expenses. It is good that there is a code of conduct for the Ministers. We have the case of Orissa where the Chief Minister had his business while in Government Mere admonitions of fine of Rs 4000 or 5000 will not do: there will have to be stern punishment. There should be a high standard among the public also. A corrupt man, more so in high places, should be put to public shame. I am of that opinion. Merely bringing litigation will not help or merely giving him some small punishment will not help. Corrupt people should be put to shame and should not be allowed to stand anywhere in public life. In the olden days, they were publicly flogged and they were made to sit on the back of donkeys.

16 hrs.

AN. HON. MEMBER: Black faces.

SHRI NARENDRA SINGH MAHI-DA: Yes; what I mean to say is, the punishment should be so severe that they may not re-enter public life. I therefore welcome this Bill, and I hope our standards will improve and no Minister in any State or at the Centre will dare indulge in any sort of corruption.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): Sir. I should like to congratulate the Government on bringing this Bill, which should be of good service with regard to the eradication of corruption in society. Actually, after Independence, corruption appears to all-prevading. With have become regard to Ministers, Gandhian principles are completely forgotten. The amount of corruption that was prevalent previously in some places has now multiplied itself.

But the main thing that arises in this connection is, is this Bill complete, and would it be successful in eradicating corruption? In my opinion, it is not complete in the sense that it does not provide for defferent punishment. That is a very important point. If somebody is found guilty, all that is done in the case of a civil servant is that he is made to retire prematurely or something is done to hush up the whole matter. The consequence is that the man does not worry, especially when he has built up sufficient fortune by wrong methods. He feels that the ultimate punishment is not going to be severe and so, why bother about it?

We have seen recently the report of the CBI, and it is found that about 99 per cent of the cases deal with small petty clerks or some supervisory grade staff. But when it comes to the higher ranks of the service, the CBI probably takes a lenient view or it does not make sufficient efforts to bring them to book. Even if they

are brought to book, they are transferred or a mild punishment is given. I think the Service Rules should also be amended, so that a civil servant may feel that if he goes corrupt, he is going to be punished and the punishment is going to be very stiff; and that would make him afraid of indulging in these acts.

Another important point which I would like to emphasise is with regard to public undertakings. That is a field where I have some experience. I am sorry to say that in that field also, corruption exists. It may not be in a big way, but it is there; there is no doubt about it. Part of the losses, if you analyse them, would be traceable to corruption. I may give In respect of a leading an instance. concern, the iron and steel goods are despatched by wagons. They reach their destination, and subsequently a note goes that the goods are defective; discounts and rebates for unjustified claims are given and considerable loss is insurred. This can be heard in the markets of big cities. (Interruption)

SHRI R. K. BIRLA: Why not you name the company?

SHRI S. S. KOTHARI: It is there; in the public sector. For instance, the Hindustan Steel. Let them look into it, if they have got the courage. In this case, discounts and rebates are claimed, and part of the claim is false or is exaggerated and a greater amount is paid than what is justified. That is one of the reasons why losses in such large concerns occur. Then, in respect of a concern in Bhopal, some bogus purchase bills have been entered in the books. It came to my notice that such things were indulged in. I hope that this will be looked into.

So, I would submit that with regard ' to public undertakings also, strict rules should be prescribed. Besides, efforts should be made to investigate

1905 (Ai) LS-17.

515 Lokpal and

[Shri S. S. Kothari]

and locate where corruption is taking place. With regard to agreements entered into by public undertakings, so many cases have come to light. I have introduced a Bill to the effect that public undertakings agreements should be properly scrutinised. But this Government does not want to take any action whatsoever. Wrong agreements are entered into, and even where the persons who had entered into those agreements are caught, they are allowed to go scot-free, and to join the very concerns and the contracting parties in whose fayour they acted in a corrupt manner.

Therefore, unless the Government is seriously inclined to end corruption and unless the highest ranks in the civil service feel that it is their duty to see that their subordinates and other officers in the public undertakings do not resort to corrupt methods, I think any amount of Bills, and any amount of rules which are framed are not going to eradicate corruption. The spirit must be there; the will must be there. Most of the civil servants, who are in the higher echelons, are good honest people. They have come after much filtering. They must make it a point not to condone corrupt officers in their department but in the interest of the country, they must take action and end corruption.

Even with regard to the armed forces, I am sorry to say that cases are brought to light where goods are supplied to armed forces which are defective. If even military goods are defective, we can imagine to what extent degradation has taken place and how much corruption is pervading in society. In the case of the armed forces, I would think that the forces should have the power to take the strongest possible action against any person who is found to be corrupt: because if corruption exists in forces, I do not know the armed where it would lead this country to.

I have already dealt with the masistracy. Then I would say that an-

onymous complaints should not be excluded. It is an important point. I would suggest that a Committee of Parliament should be attached to the Lokpal and that Committee should examine whether there is a prima facie case or not. I feel that is necessarv because the Lokpal is likely to be flooded with complaints and it will not be able to act properly. On the other hand, if there is a committee which can sort out the complaints, review them and, where a prima facie case appears to exist forward them to the Lokpal. That would ensure that the Lokpal is not over-flooded with complaints.

Lastly, the success of this measure would depend largely upon the quality of the Lokpal or Lokayukta himself, They should be men of integrity, enjoying the highest possible standing in public life, with a reputation for absolute honesty. Only such people should be appointed to these posts and it should be seen that they are not influenced by any person whatsoever. Because if they are influenced, they will not be able to do justice to their job and the whole structure of the institution of Lokpal and Lokayukta, which we are trying to build, would be jeopardised.

SHRI P VISWAMBHARAN (Trivandurm): Mr. Chairman, this is a very inadequate piece of legislation. It does not satisfy the requirements obtaining in of the situation this As has been stated country today. earlier, corruption is now all-pervading. Till a few years ago we used to hear stories of corruption only among Congressmen and Congress Ministers. Now that every party in India hascome into power in one State or another, the disease of corruption has spread into all parties. I confess that I also belong to a party which has got some partnership in administration in the State of Kerala. It is a sorry state of affairs that corruption has become so common and there is

no party which is free from that. All the same, I hold the Congress entirely responsible for the present state of affairs, because if they had given a clean administration during the last twenty years this disease would not have spread to the other parties.

The main adequacy of this Bill is the exclusion of the Prime Minister and Members of Parliament from the purview of this Bill. In my State of Kerala, the Public Men Inquiries Bill is before the State Assembly, When the Select Committee reported on that Bill, it included the Chief Minister, members of the State Legi3lature and the members of the panchayat samity and similar bodies within the purview of that Bill. But, after the report of our Joint Committee has come up, an attempt is being made to exclude the Chief Minister and the members of the legislature on the plea that they are excluded in the Lokpal and Lokayukta Bill.

The Minister, while replying to my amendment for the inclusion of Members of Parliament, did not give any reason; he simply said that this was considered by the Joint Committee and this suggestion was rejected. The entire Bill was considered by the Joint Committee. So, it is not a proper ground to be advanced here. Anyway, this inadequacy is there and this has got to be removed and it should be made more perfect.

Still, as a step in the right direction, I welcome this Bill and I request the Government to give a trial to this Bill, as has been said by Shri Kothari, by a sense of integrity and cent per cent respect should be given to the recommendations of the Lokpal and the Lokavukta. Under the Bill the Lokpal or the Lokayuktas could only make recommendations and it is for the competent authority to act. The competent authority is the Prime Minister or other competent authorities appointed by the Government. If those authorities fail to act according to the recommendations of the Lokpal or the Lokayukta, he can only

make a special report to the President. A special report to the President only means a report to the Government under the present sy3tem of our government. So, it is up to the Government to act on the recommendations or reports of the Lokpal and the Lokayuktas. I hope, the Government will give a fair trial to this and also come forward at the earliest available opportunity to include the Prime Minister and the Members of Parliament also within the purview of this enactment.

SHRI R. K. BIRLA (Jhunihunu): Sir, while I support this Bill, I would like to know from the Government whether this Bill will be applicable to the armed forces also. I have very high regard and respect for all the three armed forces-the Navy, the Air and the Army. They are the defenders of our country. We know it verv They have done a wonderful well. piece of job during the Chinese aggression as well as during the Pakistani aggression. I would like 10 know from Government whether there is going to be a separate Lokayukta for the armed forces or whether this will be applicable to the armed forces also.

Secondly, people have spoken very greatly about corruption. I know fully well that there is corruption practically in every sector, whether it is the public sector or the private sector, whether it is a Government official or a private official. What is the reason for this corruption? Why should there be such a great corruption in our country? The reason is that we produce less; there is less production of every article which is consumed by human beings.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: And poor distribution too.

SHRI R. K. BIRLA: Just a minute.

So, the first job for we people here is that we must produce more and to the maximum. We must generate wealth in the country, whether it is in the private sector o_{i} in the 19 Lokpal and

[Shri R. K. Birla]

public sector, whether it is by me or by my hon. friend who just now interrupted me. There must be more wealth in the country. The more the wealth in the country, I can tell you, there is going to be less and less corruption. That is all I have to say.

भी रामाबतार झास्त्री (पटना) : यह जो बिल है इसमें यत्नतत्न खामियां रह गई हैं। लेकिन मोटे तौर पर यह बिल सही है ग्रीर हम इसका समर्थन करते हैं।

इसका समर्थन करते हुए मैं एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं । यह सही है कि जब तक हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में ग्रामल परिवर्तन नहीं होगा. पंजीवादी व्यवस्था को छोड कर समाजवादी रास्ते पर चलना हम शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार का श्रन्त नहीं कर सकेंगे । लेकिन जब तक वह स्थिति नहीं ग्राती है तब तक यह बिल भ्रष्टाचार पर अंकूश लगाने का काम करेगा । लेकिन यह तभी होगा जब इस बिल को किताब के पन्नों में ही बन्द करके नहीं रख दिया जाएगा । ग्राप जानते हैं कि हमारे देश में मजदूरों के लिए, हरिजनों के लिए बहत से कानुन बने हुए हैं लेकिन उन पर ग्रमल न होने की वजह से उनको अपना हक नहीं मिल पा रहा है । उनको जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है । इसको हम ग्रौर ग्रांप ग्रच्छी तरह से जानते हैं। इस विल के साथ भी ऐसा ही किया गया तो इस में बहत सी ग्रच्छी बातें होते हए भी इसका कोई लाभ नहीं होगा । उस ग्रवस्था में हम इसका प्रयोग भ्रष्टाचारियों को पकडने में, घस लेने वालों को पकडने में, समाज विरोधी काम करने वालों को पकडने में नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हं कि इसको ठीक तरह से कार्या-न्वित किया जाए, इसको काम में लाया जाए । तभी हम, जो हमारा सीमित उद्देश्य है, उसको हासिल कर सकेंगे ।

जो हमारा उद्देश्य है उसको हासिल करने के लिए इस बात की भी ग्रावध्यकता है कि लोकपाल बहुत ही ईमानदार हो । इसको कई ग्रन्थ माननीय सदस्यों ने भी कहा है । उसको ईमानदार ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसको जनता से भी सम्पर्क रखना चाहिए भौरे जनता की मुसीबतों को समझने वाला भी होना चाहिये, उसकी दिक्कतों को समझने वाला भी होना चाहिये । इसके साथ-साथं उसको जात बिरादरी, फिरका-परस्ती, सम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर काम करना चाहिए । भगर वह इन सब बराइयों से ऊपर नहीं होगा तो उसका जो पवित कत्त्तंव्य है, उसको वह निभा नहीं सकेगा । हम ग्रौर ग्राप जानते हैं कि पिछले दिनों बहत बड़े-बड़े सरकारी अफसरों ने साम्प्रदायिक भावना में बहकर साम्प्रदायिक दंगों में भाग लिया । इसका सबत रांची का दंगा है या कोई ग्रीर जगह का दंगा है । इस वास्ते लोकपाल को ईमानदार हो नहीं होना चाहिये, नौकरशाहियत से दूर ही नहीं होना चाहिये, बल्कि जातपात और फिरका-परस्ती की भावना से भी ऊंचा उठना चाहिये । वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो पक्के तौर पर धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हो । वह भ्राष्टाचारी भी नहीं होना चाहिंये । ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि आज जिन बडे-वडे नेताओं के हाथ में इस देश की बागडोर है कल को उनको ग्रगर जनता ग्रपने बीच में से निकाल दे यानी चनाव में हरा दे तो शुक्ल जी उन लोगों में से किसी को लोकपाल नियुक्त कर दें। गप्पा साहव जैसे किसी व्यक्ति को लोकपाल बना दें ग्रौर फिर वह वहां पर जा कर गोलगप्पे बांटने शरू कर दे । उसको पार्टीवंदी से उपपर उठकर काम करना चाहिये । लोकपाल किसी पार्टी विशेष के प्रभाव में नहीं होना चाहिये, किसी मंत्री विशेष के प्रभाव में नहीं होना चाहिये, किसी बडे ग्रफसर विशेष के प्रभाव में नहीं होना चाहिये ।

521 Lokpal and

16,16 brs.

[SHRI PRAKASH VIR SHASTRI in the Chair]

म्राज क्या होता है ? हमारे देश में एंटी कूरप्शन डिपार्टमेंट बने हुए हैं। लेकिन उनके द्वारा बडे लोग नहीं पकडे जाते हैं। जो छोटे-छोटे कर्मचारी होते हैं उन बेचारों को कहा जाता है कि तुमने पांच रुपये घस ली है, दस रुपये घुस ली है और उनको पकड़ लिया जाता है ग्रौर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है । मुझे ग्रपने सुबे का अनुभव है। एक एस डी स्रो के मामुली पेशकार ने पांच रुपये घुस ली और उसको दो साल की सजा करवा दी गई ग्रीर उसकी नौकरी कीन ली गई। ऐसान हो कि बडी मकलियां कट जायें भीर छोटी मछलियों को **पकडने लग जाएं ।** ग्रगर लोकपाल ठीक नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, इन सब बातों से ऊपर नहीं होगा, जनता के सुखदुख को समझने वाला नहीं होगा तो बह इस तरह की गलतियां कर सकता है जो साधारण कर्मचारी हैं उनको तो पकड लिया जाएगा श्रौर जो बडे लोग हैं वे बच जायेंगे । बहुत से लोग कहते हैं कि छोटे लोग कचहरियों में पैसे मांगते हैं। ऐसे मामले भी कहीं-कहीं होते होंगे । लेकिन इसका इलाज यह है कि उनको ग्राप जीवनयापन योग्य पैसा दें. मिनिसम वेज ग्रावश्यकता के ग्राधार पर दें। उनकी तरफ से यह मांग उठाई जा रही है। 27 लाख केन्द्रीय कर्मचारी इस मांग को लेकर ग्रान्दोलन कर रहे हैं । 19 सितम्बर, 1968 को उन्होंने हड़ताल भी की थी। उनकी जो दिक्कतें हैं उनको श्राप दूर करें । उनकी दिक्कतों को ग्राप दूर नहीं करेंगे लेकिन वे ग्रगर कुछ गलती करेंगे तो ग्राप उनको पकड लेंगे । बड़े-बड़े मगरमच्छ जो हैं, बड़ी-बड़ी मछलियां जो हैं वे तो बच जाएंगी जैसाकि हम अपने सूबे में देख रहे हैं लेकिन ये पकड़ लिये जायेंगे । ये वे मगरमच्छ हैं जिन्होंने लाखों और करोड़ों रुपया हडप लिया है।

मेरा निवेदन है कि सरकार इस विष्ठेयक को लाग करते समय इन तमाम बातों को ध्यान में रखे ग्रौर पूंजीवादी समाज बनाने की अपनी वर्तमान नीति को तिलाजलि दे दे। यह ग्रच्छा है कि उसने बैंकों का राष्टीयकरण कर दिया है । उसके बाद वह विदेशी व्यापार का भी राष्टीयकरण कर दे। ग्राज बंगाल में चाय बागान में, जो कि अंग्रेज पूंजीपतियों के हाथ में हैं, दो लाख मजदूरों की हडताल चल रही है । सरकार उन टी प्लान्टेशन्ब को भी हाण में लेले । इसी प्रकार वह विदेशी तेल कम्पनियों ग्रौर गल्ले के थोक व्यापार को भी अपने हाथ में ले ले । पब्लिक सेक्टर में जो स्टील के कारखाने हैं, उनके ग्रतिरिक्त प्राईवेट बेक्टर में टाटा बैठे हुए हैं, जिनका चाबूक राष्ट्रपति के चुनाव में चल रहा है । सरकार इन कारखानों का भी राष्टीयकरण करे।

यदि सरकार सचमुच में ये कदम उठा कर समाजवाद की तरफ़ बढ़ेगी और भ्रष्टाचार का श्रन्त करेगी, तभी इस विघेयक के सीमित अटेक्य की पूर्ति होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विश्वेयक का समर्थन करता हं।

श्वी श्रस्टुर गनी दार (गुड़गांव) : सभापति महोदय, मैं यह बिल लाने के लिए सिदकदिली से श्री भुक्ल को मुबारकबाद देता हूं । इतिहास में उनके नाम के साथ हमेशा इस बिल का जिक किया जायेगा, जिसके पास होते ही, मेरा यकीन है, पचास परसेंट करप्शन ग्रपने ग्राप खत्म हो जायेगी । ग्राखिर हुकूमत का एक जलाल होता है, वर्ना बीस सिपाही कैसे लाखों ग्रादमियों को सम्भाल सकते हैं । इस बिल को लाने के मानी ये हैं कि गवनमेंट करप्शन को खत्म करने पर तुल गई है ।

यह ठीक है कि इस बिल में लुटियां हैं मैं चाहता था कि यह कानून हम पर लागू हो ग्रौर प्रधान मंत्री पर भी लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । मैं बताना चाहता हूं कि किसी बक्त प्रधान मंत्री का ईमाल पराल [श्री ग्रब्युल गनी डार]

खयाल यह था कि पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर ने एब्यूज ग्राफ़ पावर नहों किया ग्रीर वह नेक हैं, जबकि हमारा विचार था कि उन्होंने एब्यूज ग्राफ़ पावर किया । प्रधान मंती जेंने हमें बहुत कुछ कहा । लेकिन ग्रदालत क्वेंका फ़ैसला प्रधान मंती के ख्याल के खिलाफ़ था ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह जरूरी नहों होना चाहिए कि कोई एलोगेशन्ज करे ही, तभी लोकराल उन पर तवज्जह दें । कई बातें सखबारों में क्रा जाती हैं । मैंने 19 मार्च के स्टेट्समैन में एक निराली खबर देखी । दिल्ली एडमिनिस्ट्रेगन ने प्रपनी को-प्रापरेटिव कन-ज्यूमर्ज सोसायटी के माडिट के लिए एक ऐसे त्रखन को ग्राडिटर मुरूरेर किया, जिसकी काफ़ी ग्ररसे से गवर्नमेंट के यहां इज्ज्ज्त है । उसने 1966-67 की रिपोर्ट ग्रगस्त, 1968 में दे दी । मैं कोई सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हू, लेकिन उस रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत सी गलतियां हैं ।

इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं होना चाहिए कि कोई अपनी ऐलीगेशन्ज लिख कर मेजे और यह भी जरूरी नहीं होना चाहिए कि वह अपना नाम लिखे। अगर लोकपाल या सरकार के नोटिस में इस किस्म की कोई बात या जाये, तो उसके बारे वे जरूर तहकीकात की जानी चाहिए।

मेरे दोस्त, झा साहब, ने बार-बार बडे बड़े मगरमच्छों का जिक किया है। गवर्नमेंट को इस बात का पता लगाना चाहिए कि अगर किसी ने सनग्रत को तरक्की देने के लिए. मजदूरों को काम देने के लिए या फ़ौज या. पुलिस को वर्दी वगैरह देने के लिए नाइलोन ग्रौर वुल टाप्स को इम्पोर्ट किया, तो क्या उस कच्चे माल का उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया । मेरे जैसा ग्रादमी इस बारे में किताबें और सुबुत वगैरह कहां से लाये ? सरकार इलैक्ट्रिटी की किताबें मंगाये । वे सरकारी किताबें हैं मौर उनको बदला नहों जा सकता है । ग्रगर इलैक्टिसिटी का कनजम्प्शन हुग्रा है, तो यकीनन उस माल को उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए उसको इम्पोर्ट किया गया था। चाइना के साथ लडाई के वक्त डिफेंस के नाम पर पचास लाख रुपये के नाइलोन ग्रीर वुल टाप्स मंगाये गये थे, लेकिन डिफेंस के लिए घेले का भी इस्तेमाल नहीं किया।

खुदा शुक्ला जी को मेरी जिन्दनी दे । उनकी गवनमें कामयाब हो । ग्रगर वह मुझे कहें, तो मैं एक खाका दे दूंगा कि किसने ब्लैक में कितना रुपया कमा लिया । उस रुपये में से कुछ तो उन लोगों की जेब में गया, कुछ प्रफसरों की जेब में गया ग्रौर कुछ एक-प्राध मिनिस्टर या दस मिनिस्टरों, की जेब में गया ।

ग्राखिर में मैं ग्रापका शुकिया ग्रदा करता हूं ग्रौर शुक्ला जी के लिए चाहता हूं कि मेरी उम्र उन्हें लग जाये ग्रौर वह नेक काम करते रहें।

[شری عبدالغلی قار (کورکاؤں) -سیپیتی مہودیہ - میں یہ بل لانےکے لیے مدق دلی سے شری شکل کو میارکیاد دیتا ہوں - انہاس میں ان کے زام کے ساتھہ عمیشہ اس بل کا ذکر کیا جاتھا۔ جس نے پاس ہوتے ہی - میرا یقین

ریورت اگست، ۱۹۱ میں دے دی۔ میں كوئى ستثات شيد استعمال لهين كرنا چاهتا هين - ليکن اس ريورت • ين بتایا گیا که بہت سی فلطیاں هیں –

رحسترار صاحب نے یہ سمجھ کر کہ اكر كورنمذت تك وة ريررت جائيكي -تو کافی نقصان هوکا - اس رپورت کو دیا دیا - حالانکہ اس کے لئے آفتر کو ++۱۵ روپیے کی فیس دی گئی تھی ۔ اس کے بعد رجسترار صاحب نے بااکل ایے سالے کو - ساری خدائی ایک طرف -بھری کا بھائی ایک طرف - آنڈر مقرر کر دیا - بہلے آدثر کو ++ ۱۵ روپے فیس دی - لیکن اس کی رپورت غائب کر دی اور اس کے بعد دوسرے آتار کر پھر فیس دے کر نئی رپورے تهار کروا لی -

اس لئے میں نہذا چاہتا۔ ہوں کہ یه ضروری نهپن هونا چاهیئے که کوئی ایدی ایلیگیشنس لکه کر بهیچے زریه بھی ضروری تھیں۔ ھوتا چا<mark>ھڈے کہ۔ 8</mark> آیغا نام لکھے - اگر لوگ پال یا سوکار کے نوٹس میں اس قسم کی کوئی بات آ جائے - تو اس کے بارے میں ضرور تحقیقات کی جانی چاہئے -

میرے موست - جها صاحب - نے بار بار بوے بوے مگرمچھوں کا ذکر کیا **ہے - گورنمڈ ت کو ا**س بات کا پتھ الگا ا چاہئے کہ اگر کسی نے صنعت کو ترقی دیئے کے لئے - مندوووں کو کام دینے کے لئے یا فوج پاپولیس کو وردی وفیرہ دینے کے لئے

ہے - بیجاس برسیدت کریشن اپنے آپ ختم هو جانے کی - آخر حکومت کا ایک جلال ہوتا ہے - رزنہ بیس سہاھی کیسے الکھوں آدمسیوں کو سلبھال سکتے ھیں ۔ اس بل کو لانے کے منٹی ایم هیں کھ گورنمانے کرپشن کو خام گرنے ير تل گئی ہے۔

یہ تھیک ہے کہ اس بل میں ترقيان هين - مين چاهتا تها كه ايد قانرر. ير لاکو هو اور پردغان منتبىهم پر بهي الأو هو - ليكن أيسا تهين كها قها-ميو، بتانا چاهنا هون که کسی وقت يودهان منترى كا إيماندارانه خهال يه تواکه پنجاب کے چیف مذلبار نے ايمپوز آف ياور شهين کيا اور وه نيک هيں - جبکه عمارا وچار تھا که انہوں نے ایمیوز آف پاور کیا - پردھان ملتری نے همیں بہت کچھ کہا - لیکن عدالت کا فیصلہ پردھان منتری کے خیال کے خلاف تها -

مين کهنا چاهتا هرن که به ضروري نهیں هونا چاهئے که کوئی اینیگیشن کرے ھی - تبی لوگ پال ان پر توجه دیں - کئی باتیں اخبارں میں آ جاتی ہیں - میں نے 19 مارچ کے ستيتاسين مين ايک نوالي څېو دیکھی - دھلی ایڈمنسٹریشن نے ایلی فوآپریٹرو کلزپرمارز سوسائٹی کے آڈت کے لئے ایک ایسے شخص کو آدثر مقرر کیا جس کی کافی عرصے ہو گونیدے کے یہاں عزت کے بدارس نے ۲۷-۱۹۱۹ کی ناژلون اور وول شالهي کر امهورت کيا -تو کنا اس کنچے مال کا اس مقصد کے لئے استعمال کیا گیا۔ مہرے جیسا آدمی اس بارے میں کتابیں اور ثبوت وغيرة كهان سے لائے - سركار أيليكتريستي کی کتابیں ملکایئے - وہ سرکاری کتابیں همن أور إن كو بد لانهين جا سكتا ه-اگر ایلیکتریستی کا کنزمیشن هوا هے تو یقیداً اس مال کو اُس مقصد کے لئے استعمال کہا گیا ہے - جسکے لیے اس کو امیہرے کیا گیا تھا ۔ جانا کر ساتھ لوائے کے وقت ڈینیلس کے نام پر یچاس لاکھ رویڈے کے نائلوں اور وول قايس ملكائے كئے تھے - ليكن آيديلس کے لئے دھیلے کا بھی استعمال نہیں کیا گیا ۔

خدا شکلا جی کو میری زندگی دے -ان کی گورندقت کامیاب هو - اگو ولا مجھ کہیں تر میں ایک خاکدےدرنگا که کس نے بلیک میں نقلا روپیه کیا لبا - اس روپیے میں سے کچھ انسروں لوگوں کی جیب میں گیا کو کچھ ایک آدھه منستر - یا دس منستروں - کی جیب میں گیا

آخر میں میر ، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اوو شکلا جی کے لے چاھتا ہوں کہ میری عمر انہیں لگ جائے اور وہ نیک کام کرتے رہیں -]

श्री वेणी शंकर शर्मा (बंका) : सभापति महोदय, इस बिल के मूलभूत सिद्धान्तों से ग्रपनी सहमति प्रकट करते हुए मैं इस का स्वागत करता हं। मेरे विचार में यह बिल बहत पहले भा जाना चाहिये था, क्योंकि बिना बोजना क्रीर प्लानिंग के भारतवर्ष में अगर कोई चीज बढ़ी है श्रौर पनपी है तो वह है भ्रष्टाचार, बेईमानी, शैतानी ग्रौर घुंसखोरी । इस का एक कारण यह भी है कि चंकि हमारे बहां प्राडक्शन की कमो है, इसलिए प्रापर डिस्टीब्युशन के लिए हम ने एक तरह से लाइ-सेंस ग्रौर परमिट का राज्य कायम कर दिया , जिसकी वजह से हमारे यहां भ्रष्टाचार ग्रौर घुंसखोरी बढ़ी । जहां हम इस बिल के द्वारा . भ्रष्टाचारियों को सजा देने की बात सोच रहे हैं, बहां हमें भ्रष्टाचार के कारणों को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि हम लाइसेंस ग्रौर परमिट की व्यवस्था को बन्द नहीं करते हैं, तो अब्टाचार बढ़ता ही रहेगा ग्रौर चाहे हम कितने ही लोकपाल ग्रौर लोका-युक्त नियुक्त करें, यह बीमारी दूर नहीं होगी । माननीय खाद्य मंत्री ने एक बार कहा था कि चूंकि खाद्य स्थिति सुधर रही है हम श्रागे चल कर फूड जोन्ज को हटा देंगे । मैं समझता हूं कि ऐसा करने से कम से कम एक विभाग में भ्रष्टाचार में तो कमी हो जायेगी।

प्राइम मिनिस्टर और पालियामेंट के सदस्यों को इस बिल की परिघि में नहीं रखा गया है । मेरी दृष्टि में यह एक ऐसा कदम है, जिसके लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा । प्राज तो यह ग्रवस्था हो रही है कि बाड़ ही खेत को खा रही है । जो हमारे रक्षक हैं, वे ही भक्षक हो जाते हैं । मैं प्राइम मिनिस्टर की व्यक्तिगत क्रूप से बात नहीं कहता हूं, बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर के मोहदे की चर्चा करता हूं । ग्राज ूकी प्राइम मिनिस्टर ग्राच्छी हैं । पहले के प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ग्रच्छे थे । लेकिन ग्रागे चल कर ऐसे प्राइम मिनिस्टर ग्रा सकते हैं, जिन के ग्राचरण के बारे में सन्देह हो । इसलिए प्राइम मिनिस्टर ग्रौर पार्लियामेंट के सदस्यों को इस बिल के कार्य-क्षेत्र से मुक्त रखना बहत खतरनाक होगा। क्योंकि पालियामेंट के मेम्बर भ्रगर मक्त हो जाते हैं तो एम॰ एल॰ एज॰ भी स्टेटेस के ऐसे बिलों के दायरे से मुका कर दिए आऐंगे और जीफ मिनिस्टर्स भी छोड दिए जाएंगे । यह भी हमने देखा है कि भ्रष्टाचार ग्रौर घुंसखोरी के मामले में. लाइसेंस ग्रौर परमिट दिलाने में जितने एम० पी० भौर एम० एल० एज० दक्ष होते हैं भौर वे जितना मागे पीछे काम करते हैं उतना भौर कोई नहीं करता। इसलिए कम से कम इस बिल का उद्देश्य पूरा हो ग्रौर इस बिल से देश को लाभ हो इस के लिए मैं चाहंगा कि पालियामेंट के मेम्बर झौर प्राइम मिनिस्टर को भी इस बिल की परिधि में शामिल किया जाए श्रौर जब यह होगा तो यह निश्चित है कि जो स्टेटस में कानन बनेंगे उस में जो एम० एल॰ एज॰ हैं ग्रीर चीफ मिनिस्टर्स हैं वे स्वयं ही उनके दायरे में ग्रा जाएंगे। इस बिल के दायरे से प्राइम मिनिस्टर ग्रौर मेम्बर्स ग्राफ पार्लियामेंट को ग्रलग कर देने से मैं समझता हं स्वभावतः स्टेटस में भी चीफ मिनिस्टर्स ग्रीर एम० एल० एज० ग्रलग रखे जाएंगे। इतनी बढी संख्या में राजनीतिज्ञों को इस बिल के दायरे से ग्रलग रखना मैं समझता हं बहत बरा होगा ग्रौर इसलिए मैं माननीय गह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इन दोनों बातों पर वे फिर से विचार कर के इन्हें स्वीकार करेंगे । क्योंकि ग्रन्त में जो राम राम करता है उसी की मक्ति होती है। इसलिए यदि बिल के इस तृतीय वःचन में भी वह इस को मान लेते हैं तो देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति जी, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ग्राभारी हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से इस विघेयक का समर्थन किया है । माननीय रंगा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि इस में प्रधान मंत्री जी को शामिल करना चाहिए था । प्रधान मंत्री जी को क्यों हम शामिल नहीं कर सके

इस विधयक के अन्तर्गत इस के बारे में काफी विस्तत रूप से यहां पर बताया गया है ग्रौर में समझता हं कि उस के बारे में एक जनरल ऐग्री-मेंट भी है कि प्रधान मंत्री के पद को इसमें शामिल करने से बहत सी ऐसी कठिनाइयां पैदा होंगी कि जिस से हमें इस बिल को लागू करने में बहत कठिनाई होगी । मैं यह बात साफ कह देना चाहता हं कि यह बात नहीं है कि देवर्तमान प्रधान मंत्री इस बिल में प्रधान मंत्री के पद को सम्मिलित नहीं करना चाहतीं । इस के विप-रीत वर्तमान प्रधान मंत्री यह चाहती थीं कि किसी तरह से इस बिल में प्रधान मंत्री को सम्मिलित कर लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा। पर जब हम ने उन को बताया कि क्या **कारण हैं, किन कार**णों से हम झामिल नहीं कर रहे हैं तब उन्होंने कहा कि ठीक है. न शामिल किया जाये । यदि देखा जाय तो उन की रुचि तो इस बात में थी कि इस बिल में प्रधान मंत्री को भी सम्मिलित करना चाहिए । पर जैसे कि कारण पहले बताए गए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, उन कारणों से इस बिल में प्रधान मंत्री को शामिल करना ग्रावश्यक नहीं समझा गया और मैं समझता हं कि उन को शामिल करने से हमारा जो बिल का उद्देश्य था उस में बहत हानि होती ।

श्वी बाकर ग्रली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : चीफ मिनिस्टरों का क्या होगा ?

भी विद्या चरण शुक्सः वह तो राज्य सरकारें जब प्रपने प्रपने कानून बनाएंगी तो उस में वह प्रावधान करेंगी। केरल में उन्होंने कानून बनाया है तो उस में उन्होंने चीफ मिनिस्टर को सम्मिलित किया है। दूसरी जगह वह कानून बनाएंगे तो स्वयं निर्णय करेंगे कि उन्हें शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।

रंगाजी ने दूसरी बात यह कही कि हमें यह देखना चाहिए कि इस की कीमत कहीं इतनी ज्यादान हो कि गरीब लोग इस प्राव-धान का फायदान उठा सकें और दूसरी बात

[श्री विद्यं चरण शुक्ल]

यह कि इसमें इतनी देर न हो इस काम में कि जिससे काम की उपयोगिता ही नष्ट हो जाय। हम लोग इस का घ्यान रखेंगे और इस बिल के अन्दर जो प्रावधान किया है उसमें भी यह बात है कि कम से कम खर्चा हो और जल्दी से जल्दी इन चीजों का निर्णय हो सके। जब तक जल्दी निर्णय नहीं होगा तब तक इस बिल का जो प्रमुख उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री शिव चन्द्र झाने ग्रपनी बहस शुरू करते हुए कहा कि इस बिल का मतलब यह होता है कि बहुत ज्यादा अष्टाचार हमारे देश में फैला हुआ है। मैं इस वात को नहीं मानता हं कि यह बिल इस बात का सबत है कि भ्रष्टा-चार बहुत ज्यादा देश में फैला हम्रा है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य केवल अष्टाचार को हटाना ही नहीं है। इस बिल का उद्देश्य यह भी है कि जो अनाप शनाप आरोग गैरजिम्मेदारी से लगाए जाते हैं उन का भी इलाज इस के द्वारा हो क्योंकि जब लोक पाल मौर लोकायुक्त के पास इस तरह की चीजें जाएंगी तो वह इस बात का फैसला कर सकेंगे कि जो मारोप लगाए गए हैं उन में कोई सत्यता है या नहीं, उन में कोई तथ्य है या नहीं। या बिलकुल ही निराधार भ्रौर गलत म्रारोप लगाए गए हैं। ग्र.ज इस तरह की कोई एजेंसी या मशीन हमारे पास नहीं है। ग्राज यदि किसी मिनिस्टर या अधिकारी पर कोई आरोप लगाया जाता है तो सरकार को स्वयं निर्णय करना पड़ता है कि प्राइमा फेसी कोई केंस उसमें है या नहीं. कोई इस तरह की गुंजाइश इस के ग्रन्दर है या नहीं कि इस के लिए कोई नियमित रूप से जांच पड़ताल की जाय या नहीं। पर जब लोकपाल ग्रौर लोकायक्त की संस्था हमारे सामने ग्रा जायगी तब इस बात की सुविधा हो जायगी कि हर एक मसले को जो कि उन के कार्यक्षेत्र के ग्रंतर्गत ग्राता है उस के ग्रन्दर हम इस को भेज सकें और उनके द्वारा इस की जांच पडताल कदना लें कि जो भी संसद सदस्यों ढारा या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा ग्रारोव

लगाए गए हैं उनमें कितना तथ्य है झौर उस से आगे हम लोग क्या कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए यह कहना कि यह घ्रध्टा-चार जितना बढ़ा हुआ है उस को यह बिल दिखाता है यह बात नहीं है। यह गैर जिम्मे-दारी के जो आरोप लगाए जाते हैं सार्व-जनिक कार्यकर्ताओं के ऊपर और सरकारी अधिकारियों पर जो कि एक कटिन कार्य का निर्वाह करते हैं इस देश के अन्दर, उनके ऊपर से वह सन्देह दूर हो सके इस काम में भी यह विधेयक सहायक सिद्ध होगा।

कोठारी जी ने यह कहा कि इस के लिए कोई संखद की एक समिति बैठा लेनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि संसद को इस बात का अधिकार है कि कोई भी उस के पास रिपोर्ट बाती है तो संसद स्वयं निर्णय कर के किसी भी समिति को स्थापना कर सकती है बौर वह तमिति उस की जांच भड़ताल कर सकती है। उस के लिए इस कानून में प्रावधान करना में तो ठीक नहीं समझता बौर न में यह समसता हूं कि वह आवाय्यक है।

जहां तन कि लोकपाल ग्रौर लोकायक्त के अधिकारियों का सवाल है कि वि स व्यक्ति को बनाया जाय उस में में समझता हूं कि जो प्रावधान इस बिल में किया गया है उस से इस बात की सुविधा होगी और हमें उस में सहायता मिलेगी कि हमारे देश के म्रच्छे से ग्राच्छे जो व्यक्ति हैं उन की इस तरह का ऊंचा पद दिया जाय । इस के लिए इस बात का प्रावधान किया गया है कि एक तो सरकार की तरफ से दूसरा विरोधी दल की तरफ से भौर तोसरा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी तरफ से कोई नाम ग्राए तो उस को मंजुर कर के हम लोकपाल का पद दें ग्रीर इसी तरह से लोकायुक्त का पद दें। इस से यह बात हम लोगों के मन में जम सवती है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से चुना जायगा वह ऐसा होगा जिस के आाचरण के संबंध

में. जिस के चरित के संबंध में ग्रीर जिस की मच्चाई के संबंध में जरा भी शक किसी को नहीं होगा भ्रीर इस की सफलता भी इसी पर ग्राधारित है। यदि लोकपाल के ऊपर सन्देह होने लगे कि किसी मंत्री या अधिकारी से वह प्रभावित हो सकता है या उन के दबाव में वह आ सकता है तब तो जो भी विश्वास थोड़ा बहत सरकार के ऊपर है कि बह प्रश्टाचार को रोकना चाहती है वह भी हट जाएगा और इस बिल का कोई मतलब नहीं रहेगा । इसलिए में समझता हं कि यह बात बहत ग्रावश्यक हैं कि जो भी व्यक्ति इस पद पर नियक्त हो वह ऐसा हो कि जिस के ऊपर सबँसम्मति से सब लोग विश्वास कर सकें ग्रीर कोई कंटीवर्सी उस के संबंध में न हो ।

बाकी रामावतार जी ने मौर दूसरे सदस्यों ने बहत लम्बी लम्बी श्रायिक व्यवस्था की बातें कहीं। मैं समझता हूं कि उन का संबंध हमारे यहां भ्रष्टाचार के जो मामले झाते हैं उन से होता है लेकिन जहां तक हमारे इस विधेमक का सबंध है इस से उस को कोई विशवे मतलब नहीं है। मैं जानता है कि उन बातों पर हमें सोच विचार करना होगा । में यह भी जानता हूं कि यह बिल स्वयं पास हो कर सम्पूर्ण रूप से जो भ्रप्टाचार के मसले हैं उन का समाबान नहीं दे सकता । उस के लिए हमें और भी दूसरे समाधान ढुढ़ने होंगे। में समझता हूं कि यह बिल उचित दिशा में एक कदम है और ऐपा नहीं हैं कि सम्पूर्णं समस्या इस कदम से तल ही जायगी । पर उचित दिशा में एक उचित कदम डोने के नाते से हमें खशी है कि उम्पूर्ण सदन ने इन विनेयक को स्वागत किया है और मैं उम्मीद करता हं कि इस विधेयक को सुर्व-सम्मति से पास किया जायगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि यह

D.S.G. (Rly.) 1969-70. विद्येयक जो संशोधित रूप में आपके सामने प्रस्तूत है, इस पर सदन अपनी स्वीकृति दे।

The Motion was adopted.

16.38 hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1969-70

ि ो ो सभापति महोदयः ग्रव यह सदन 1969-70 के रेल रे बजट संबंघो प्रतुदानों को ग्रनुपुरक मांगों पर विचार करेगा ।

DEMAND No. 2-MISCELLANEOUS EX-PENDITURE

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1970, in respect of 'Miscellaneous Expenditure'."

DEMAND NO. 15-OPEN LINE WORKS-CAPITAL, DEPRECIATION RESERVE FUND AND DEVELOPMENT FUND

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of 'Open Line Works-Capital, Depreciation Reserve Fund and Development Fund'."

इस के लिए एक घटा नियत हुआ है। जिन सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव दिए हैं ब्रौर उस पर कुछ कहना चाहते हैं वह प्रपनी चिट भेज देंजिस से उन्हें कुछ कहने का ब्रवसर दिया जाय। जो कटोती के प्रस्ताव

[•]Moved with the recommendation of the Chief Justice discharging the functions of the President.